सूर्योदय 5:37 सूर्यास्त 7:19

आज का तापमान

शिमला	17.4 न्यू	24.5 अधि
धर्मशाला	17.6 न्यू	29.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,654
निफ्टी	24,250

सोना 1,42,000 चांदी 2,19,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 30 जुलाई 2026 | 15 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 96, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

सूर्यवंशी दुनिया के टॉप-50 टी-20 बल्लेबाजों में शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली। आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। सूर्यवंशी 536 रेटिंग प्वॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। वे पहली बार टॉप-50 में आए हैं। दूसरी ओर वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे में टॉप-4 में तीन भारतीय हैं। विराट कोहली दूसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर-1 टेस्ट बॉलर बने हुए हैं। सूर्यवंशी ने पिछले सप्ताह जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज में तीन मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए। इसी प्रदर्शन की वजह से उनकी रैंकिंग में इतनी लंबी छलांग आई है। सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे।

द्रमुक विधायक के आवास पर डीवीएसी की छापेमारी

एजेंसी, करूर। तमिलनाडु में द्रमुक विधायक और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के आवास समेत छह ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) ने बुधवार को छापेमारी की। यह कार्रवाई करूर स्थित उनके घर, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टास्मैक) के जिला प्रबंधक कार्यालय और उनसे जुड़े अन्य परिसरों में की गई। डीवीएसी की टीम ने सुबह करूर के रामेश्वरपट्टी स्थित सेंथिल बालाजी के आवास पर तलाशी शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई टास्मैक में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

एजेंसी, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आठ नक्सलियों ने बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहयोग से पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में पांच महिला और तीन पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार, सभी नक्सली लंबे समय से प्रतिबंधित संगठन से जुड़े थे और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय थे। सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की नीति के तहत आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

यौन उत्पीड़न मामले में ट्रेनी आईपीएस अधिकारी काबू

एजेंसी, हैदराबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) में साथी ट्रेनी आईपीएस अधिकारी द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अट्टापुर पुलिस ने बुधवार को आरोपी उदय कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार किया। शिकायत दर्ज होने के करीब दस दिन बाद हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया और अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। मामला 18 जुलाई को दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने उत्पीड़न, हिंसा, धमकी और डिजिटल ब्लैकमेल के आरोप लगाए हैं। एनपीए ने आंतरिक जांच के बाद रेड्डी को निलंबित कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेपर लीक रोकने का कानून लोकसभा में पास

इसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना; राज्यसभा में वंदेमातरम से जुड़ा संशोधित बिल पास

एजेंसी, नई दिल्ली। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ।

इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं, अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल पास हो गया। अब जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।

वंदे मातरम के अपमान पर अब 3 साल तक की जेल

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। नए कानून में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं।

गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री नहीं देते : जितेंद्र

राहुल ने कहा कि शाह के साथ 30 गाड़ियों का काफिला था। इन्हें ये नहीं पता कि गृह मंत्री के साथ 30 गाड़ियां नहीं चलतीं और शाह विदेश नहीं गए हैं। तथ्यों के बिना गैरजिम्मेदारी से सदन में ये बातें कहना और फिर निकल जाना ये किसी नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष पीएम आवास के बाहर जाकर बैठ गए। इनकी हसरत है कि देश इनको पीएम बनाए। लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हुआ तो ये पीएम आवास के बाहर जाकर बैठ गए। जब इन्हें समझाया गया निवेदन किया कि आप यहां से हट जाइए। तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया गया। शुरू में ये प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए क्योंकि इन्हें लगा ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। लेकिन बाद में इन्हें एफओएमओ (फियर ऑफ मिसिंग आउट) हो गया।

शाह ने फायरिंग का आदेश नहीं दिया, तो सदन में आएं : राहुल गांधी

लोकसभा में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा- गृह मंत्री शाह सदन में नहीं आए, जबकि उन्हें छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए था। राहुल ने कहा- अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो उन्हें सदन में आकर साफ देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है और वह अधिकार मुझे मिलना चाहिए। राहुल ने कहा, 'राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीए नहीं हैं, हमारे मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते। वे सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखावटी है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया। शिक्षा मंत्रालय को चलाने वाला संगठन आरएसएस है।'

इराक में अमेरिकी-सऊदी कार्रवाई, ईरान समर्थित पीएमएफ के 20 लड़ाकों की मौत

एजेंसी, वॉशिंगटन। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं।

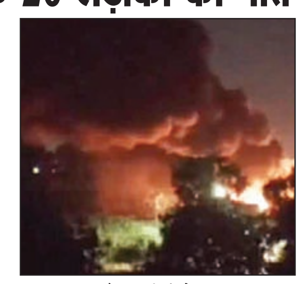

अमेरिकी सेना के मुताबिक, इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों व सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थीं, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। यमन के हूती विद्रोही रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले बाब अल-मंदेब से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की योजना पर विचार कर रहे हैं। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों ने के हवाले से दी है। सूत्रों के मुताबिक इसे कब लागू किया जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। प्रस्ताव के तहत चीनी जहाजों को इस शुल्क से छूट दी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने ईरान में हुई बैठकों के दौरान ईरानी अधिकारियों और हूती प्रतिनिधियों के बीच इस योजना पर चर्चा हुई। बाद में ईरानी सलाहकारों ने हूती अधिकारियों के साथ मिलकर टैक्स वसूलने के लिए एक संभावित व्यवस्था तैयार करने में भी मदद की। ईरान के सेना प्रमुख के डिप्टी और नौसेना कमांडर हबीबोल्लाह सय्यारी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर पर ईरानी नौसेना का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अनुमति के बिना होर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज की आवाजाही नहीं हो सकती।

इंडिगो फ्लाइट ने जयपुर के आसमान में 44 मिनट चक्कर काटे, रनवे छूकर दोबारा उड़ी

एजेंसी, हैदराबाद। हैदराबाद से जयपुर आई इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को करीब 44 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाती रही। तेज बारिश और हवा के कारण विमान को रनवे छूने के बाद दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। आखिरकार मौसम में सुधार होने के बाद विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस विमान में करीब 120 पैसेंजर थे।

इंडिगो की फ्लाइट 6E-913 बुधवार दोपहर करीब 1 बजकर 45 मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। पायलट ने निर्धारित समय के अनुसार करीब 1 बजकर 40 मिनट लैंडिंग के लिए अप्रोच भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी दौरान एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश और हवा के कारण लैंडिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन सकीं। खराब मौसम के कारण पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गो-अराउंड का फैसला लिया। ऐसे में लैंडिंग की कोशिश छोड़कर विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। विमान को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश पर जयपुर के आसपास के हवाई क्षेत्र में होल्ड पर रखा गया, जहां लैंडिंग के इंतजार में विमान लगातार गोल-गोल चक्कर लगाता रहा। इस दौरान 44 मिनट तक विमान आसमान में होल्डिंग पैटर्न में रहा। विमान के बार-बार चक्कर लगाने से पैसेंजर्स में बेचैनी बढ़ गई। कई पैसेंजर्स खिड़की से बाहर बदलते मौसम और लगातार एक ही क्षेत्र में उड़ान भरते विमान को देखकर परेशान नजर आए।

गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने की पूजा-अर्चना, शांति और समरसता की प्रार्थना

गुरु जीवन को सही दिशा देने वाले पथप्रदर्शक : रेखा गुप्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर उन्होंने भगवान के समक्ष राष्ट्र की प्रगति, दिल्ली के सर्वांगीण विकास तथा समाज में शांति, सद्भाव और समरसता की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर संत-महात्माओं एवं गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले पथप्रदर्शक होते हैं। गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं तथा समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है, जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे ऋषि-मुनियों और गुरु परंपरा ने भारत को ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति की ऐसी अमूल्य धरोहर दी है, जिसने विश्व को सदैव प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमें अपने जीवन में सत्य, सेवा, अनुशासन, नैतिकता और सदाचार के मूल्यों को अपनाने का भी संदेश देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने गुरुजनों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्लीवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की।

थाईलैंड में 3 इंडियन टूरिस्ट का अपहरण, पांच भारतीय गिरफ्तार

एजेंसी, बैंकॉक। थाईलैंड में तीन भारतीय पर्यटकों का अपहरण करके उनके परिवारों से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में पांच भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक ने तीनों को किडनैप करने को कहा था। पुलिस ने तीनों लड़कों को रेस्क्यू कर लिया है। पीड़ितों की पहचान मोहित (23), आशीष (24) और हिमांशु (20) के रूप में हुई है। आरोपियों ने उन्हें सस्ते 7 दिन के टूर पैकेज का लालच देकर थाईलैंड के पटाया शहर बुलाया था, वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक घर में बंधक बना लिया गया और उनके परिवारों से तीनों के बदले 40-40 लाख रुपए, यानी कुल 1.20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह (38), जगजीत सिंह (38), रंभालक कुमार (24), सुखबीर सिंह (37) और कुलरा सिंह (27) के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले एक महीने से चैट एप्लीकेशन के जरिए दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थे। उसी ने अपहरण की पूरी साजिश रची थी। फिरौती की रकम क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लेने की योजना बनाई गई थी।

मुख्यमंत्री ने ग्रुप-डी के 3,056 चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

खर्ची-पर्ची नहीं, ईमानदारी से मिली नौकरी : सैनी

एजेंसी, पंचकूला। हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बुधवार को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए और नवचयनित कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नवनियुक्त युवाओं के बीच आकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में खुशी और उम्मीद की नई रोशनी है। युवाओं के हाथ में पहुंचा नियुक्ति पत्र उनकी मेहनत, प्रतिभा और माता-पिता की तपस्या का परिणाम है। यह ईमानदार व्यवस्था पर लोगों के विश्वास की जीत भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवारों में आज उत्सव का माहौल है, लेकिन यह उत्सव केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे जनसेवा का संकल्प लेकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रुप-डी के 3,056 युवाओं का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, 'हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजाला है। मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। यहां खर्ची नहीं चली, पर्ची नहीं चली, ईमानदारी से नौकरी मिली है।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी नवचयनित कर्मचारी जनसेवा की भावना के साथ प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारत बाघ संरक्षण में दुनिया में नंबर-1 देश में 3,682 बाघ

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में अपनी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को और मजबूत किया है। देश में अब दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत बाघ मौजूद हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 3,682 तक पहुंच गई है, जो देश के 58 टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं। यादव ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बुधवार को एक्स पोस्ट में कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या भारत के जंगलों की बेहतर स्थिति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति लगातार किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश में संरक्षण संबंधी नीतियां और पहल प्रभावी रही हैं। उन्होंने कहा कि बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता आगे भी जारी रहेगी। जंगलों से जुड़े स्थानीय समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

सीएम बनने के बाद नहीं खरीदी कोई नई संपत्ति : सुक्खू

जमीन व मकान मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदे, बढ़ा है सिर्फ बाजार मूल्य

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पहले ही चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक की जा चुकी है और इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने बुधवार को शिमला में कहा कि रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुक्खू ने कहा कि जिस जमीन और मकान की चर्चा की जा रही है, वह उन्होंने राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदी थी। समय के साथ जमीन के बाजार मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और उसी के आधार पर संपत्ति की कीमत बढ़ी है। एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति का विश्लेषण किया गया है।

◆ चुनावी हलफनामे में पहले ही घोषित है पूरी संपत्ति

रिपोर्ट के अनुसार 31 मुख्यमंत्रियों की कुल घोषित संपत्ति करीब 3660 करोड़ रुपए है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संपत्ति सात करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। संपत्ति के आधार पर वह देश के मुख्यमंत्रियों की सूची में 17वें स्थान पर हैं। वहीं, उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में उनकी घोषित संपत्ति सबसे अधिक बताई गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी संपत्ति को लेकर अगर किसी को कोई संदेह है, तो जांच कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं और पहले भी उनकी जांच हो चुकी है। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया है और उनकी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है।

उन्होंने एडीआर रिपोर्ट में अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को भी अधूरा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए।

हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: सीएम योगी

सीएम गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गुरु पूर्णिमा पर्व संबंधी आनुष्ठानिक कार्यक्रम की व्यस्तता के बावजूद जनता दर्शन का आयोजन किया।

उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं व अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाए। बुधवार सुबह गुरु पूर्णिमा पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने करने की आवश्यकता नहीं है। सबकी समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

लोगों के प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी ने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज के इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए।

विश्व बाघ दिवस मुख्यमंत्री ने कहा- जंगल सुरक्षित रहेंगे, तो बाघ और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहेगा

प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जनभागीदारी जरूरी : सीएम धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए जनभागीदारी और प्रत्येक नागरिक के सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सिंगल-यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देकर राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करना होगा। बुधवार को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जाखन स्थित एक होटल में आयोजित 'एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन' विषयक राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यशाला नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प है। इस अवसर पर उन्होंने बाघ संरक्षण पर आधारित चित्र एवं पोस्टकार्ड का विमोचन किया और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि समृद्ध जैव विविधता और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। जंगल सुरक्षित रहेंगे, तो बाघ और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी जैव विविधता, वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण के लिए देशभर में विशिष्ट पहचान रखता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व इस प्राकृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर्यावरण, नदियों, मिट्टी, जल स्रोतों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जंगलों में छोड़ा गया प्लास्टिक कई बार वन्यजीवों के भोजन में मिल जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि वन, नदियों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के विरुद्ध निर्णायक अभियान चलाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान, 'एक पेड़ मां के नाम', नमामि गंगे और स्वच्छ ऊर्जा जैसी पहलों ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। राज्य सरकार भी पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्राकृतिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से कपड़े और जूट के थैलों सहित पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरा नहीं छोड़ने का आग्रह किया। उद्योग जगत से पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाने और युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी इशिता सजवाण, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव नीना ग्रेवाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते सहित कई अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

एससी आयोग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

रिकॉर्ड में लापरवाही और बैठक से गैरहाजिरी पर सख्त हुआ आयोग, मांगा स्पष्टीकरण

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की जिला शिमला की समीक्षा बैठक बुधवार को बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने की।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि कई विभागों ने रिकॉर्ड सही तरीके से तैयार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यदि नियमित रूप से फील्ड में जाकर कार्य करेंगे तो रिकॉर्ड स्वत: बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में लापरवाही अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से निराश्रित बच्चों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामलों की जांच गंभीरता से करनी चाहिए और यदि किसी मामले में एट्रोसिटी के आरोप साबित नहीं होते हैं तो अन्य धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए। आयोग सदस्य डॉ. विजय डोगरा ने निर्देश दिए कि एससी/एसटी विजिलेंस कमेटी की बैठकें एसडीएम स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जाएं, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को समीक्षा बैठक के निर्देशों की रिपोर्ट सात दिन के भीतर देने को कहा। बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के बजट की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जिला शिमला के लिए 25 करोड़ 43 लाख रुपए जारी किए गए, जिसमें से 23 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यानी 92 प्रतिशत बजट का उपयोग हुआ है। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी और रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर आयोग ने नाराजगी जताई। आयोग ने कहा कि बैठक से पहले रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद रिकॉर्ड लेकर नहीं आना गंभीर लापरवाही है। आयोग ने जिलाधीश को अनुपस्थित विभागाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। आयोग ने जिले में बने अम्बेडकर भवनों की स्थिति और रखरखाव की रिपोर्ट सभी एसडीएम से मांगी। बैठक में बताया गया कि जिले में पंचायती राज और शहरी निकायों में 265 प्रतिनिधि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। एससी/एसटी एक्ट के तहत वर्ष 2023 में 24, वर्ष 2024 में 37 और वर्ष 2025 में 42 मामले दर्ज हुए। बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आयोग को बताया कि अनुसूचित जाति हितों के लिए आवंटित बजट के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिला शिमला के 61 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को भारत भ्रमण पर भेजा गया। बैठक से पहले आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक में पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल के सड़क नेटवर्क को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध: हर्ष महाजन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़क संपर्क और अधोसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान हर्ष महाजन ने प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार तथा लंबित सड़क परियोजनाओं को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से पठानकोट-चम्बा-भरमौर सड़क परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत लाने और इसके कार्य को प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। हर्ष महाजन ने कहा कि यह परियोजना चम्बा और भरमौर क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने से स्थानीय लोगों को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।

सड़क और परिवहन क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। हर्ष महाजन ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल में चल रही अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं भी जल्द गति पकड़ेंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और जनसुविधाओं को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

गुरु रविदास की शिक्षाएं समाज को समानता समरसता का मार्ग दिखाती हैं: जीतराम कटवाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समानता, मानवता, प्रेम और सामाजिक समरसता का संदेश दिया तथा लोगों को कर्म, चरित्र और सेवाभाव के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जीतराम कटवाल ने गुरु रविदास महाराज जयंती वर्ष के तहत समरसता संकल्प अभियान में भाग लेते हुए कत्थ्यून और खबड़ी माता मंदिर घंडीर में पूजा-अर्चना की तथा मंदिर परिसर में औषधीय पौधे लगाए। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास के साथ सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने झंडूता विधानसभा क्षेत्र की दसलेहड़ा और झबोला पंचायतों में भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और संगठन की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

कोट कहलूर क्षेत्र में हथियारों पर रहेगा प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी जी मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हथियारों के प्रदर्शन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 13 से 23 अगस्त तक पुलिस थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार या तेजधार हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। यह प्रतिबंध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से आदेशों का पालन करने और मेले के शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग की अपील की है।

श्रावण अष्टमी मेले में नयना देवी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर व ढोल-नगाड़ों पर प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी जी के श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने 13 से 23 अगस्त तक मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन ने बताया कि मेला अवधि में किसी भी सार्वजनिक सूचना या संदेश का प्रसारण केवल मेला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों से आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

जेओए कर्मियों ने सीएम से की तैनाती जल्द देने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करुणामूलक रोजगार नीति के तहत निदेशालय भर्ती, हिमाचल प्रदेश में नियुक्त जेओए (आईटी) के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने नियुक्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें जल्द से जल्द संबंधित कार्यालयों में तैनाती प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी सेवाएं शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार करुणामूलक रोजगार नीति के तहत पात्र मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

15 अगस्त को नहीं होगी स्कूलों में छुट्टी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जब देश आजादी का जश्न मनाने के लिए तिरंगे के रंग में रंगा होगा, उस दिन हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के परिसर भी देशभक्ति के उत्साह से सराबोर नजर आएंगे। इस बार 15 अगस्त को सरकारी स्कूलों में सामान्य छुट्टी नहीं रहेगी। प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे और यहां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे सम्मान और उत्साह के साथ आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की मौजूदगी में राष्ट्रीय पर्व मनाने की तैयारियां करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में सभी उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक और प्रारंभिक) तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसरों के प्रधानाचार्यों को अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में इन निर्देशों को लागू करवाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि 15 अगस्त को सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन गरिमापूर्ण तरीके से किया जाएगा। स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अधिकारियों को कहा है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी स्कूलों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों की भागीदारी संबंधित तहसील, उपमंडल और जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में रहे।

हिमाचल पुलिस के 13 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दिन मिलेगा मानद उच्च पद

भारतेन्दु संवादददता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पुलिस के 13 पात्र अराजपत्रित अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन अगले उच्च पद का मानद रैंक प्रदान किया जाएगा। इनमें उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और मुख्य आरक्षक शामिल हैं।

पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पुलिस विभाग में लंबे समय तक समर्पण, अनुशासन और सराहनीय सेवाएं देने वाले पात्र अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन मानद उच्च पद प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय ने 12 मई, 2026 को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इसमें पात्रता, सेवा रिकॉर्ड की जांच, स्क्रीनिंग प्रक्रिया और मानद पद प्रदान करने के नियम तय किए गए। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा के बाद प्रथम चरण में 13 अधिकारियों को मानद पद देने की संस्तुति की है।

इसके तहत पात्र उप-निरीक्षकों को मानद निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षकों को मानद उप-निरीक्षक और मुख्य आरक्षकों को मानद सहायक उप-निरीक्षक का पद प्रदान किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह मानद पद किसी वित्तीय या पेंशन लाभ से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों की वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवाओं के सम्मान के रूप में दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मान और गौरव के साथ विदाई मिलेगी। पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री की इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे वर्तमान कर्मचारियों में भी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

पीजी पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 31 तक आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि एमए अंग्रेजी, एमए अर्थशास्त्र, एमकॉम, एमएससी फिजिक्स और पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर में कुछ सीटें अभी खाली हैं। इन सीटों पर प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने संबंधित विभागाध्यक्षों, पीजीडीसीए समन्वयक और वेबसाइट प्रभारी को प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की वरिष्ठता वित्तीय लाभ पर एसएलपी खारिज की

सेवा शर्त अधिनियम-2024 पर हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल सरकार को सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम-2024 को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस फैसले को प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और अनुबंध कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर कर्मचारियों का पक्ष और मजबूत हुआ है।

इस मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम-2024 पारित किया था। इस कानून के माध्यम से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए गए थे, जिन्हें कई कर्मचारियों ने अदालत में चुनौती दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल 2026 में इस अधिनियम को निरस्त करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और एसएलपी खारिज कर दी। इससे हाईकोर्ट का निर्णय प्रभावी बना रहेगा और कर्मचारियों के हितों को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है।

जुन्गा सिविल अस्पताल में 108 एंबुलेंस सेवा की मांग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जुन्गा तहसील की 12 पंचायतों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला सिविल अस्पताल आज भी 108 नेशनल एंबुलेंस सेवा से वंचित है।

आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों, विशेषकर दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निजी वाहनों या किराये के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने सरकार से अस्पताल में जल्द 108 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। सिविल अस्पताल जुन्गा में प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, जबकि हर माह 100 से अधिक मरीज भर्ती होकर इलाज करवाते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में अभी तक एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के लगभग 15 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर

▶ 12 पंचायतों के मरीजों को हो रही परेशानी मरीजों को शिमला रेफर करने की मजबूरी

असर पड़ रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर, अल्ट्रासाउंड और आधुनिक लैब जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का भी अभाव है। क्षेत्र में निजी डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को जांच के लिए शिमला जाना पड़ता है। जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने कहा कि जुन्गा तहसील के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में 108 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा करीब दो वर्ष पहले सीएचसी कोटी के लिए 108 एंबुलेंस सेवा की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है। किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ. कुलदीप तंवर ने कहा कि अस्पताल में सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति आवश्यक है।

फ्रैक्चर और गंभीर मामलों में मरीजों को शिमला रेफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 वर्ष पुराने इस अस्पताल में आज तक ऑपरेशन थियेटर के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 50 बिस्तरों की स्वीकृति है, लेकिन वर्तमान में केवल 25 बिस्तर ही संचालित हैं। क्षेत्रवासियों ने अस्पताल भवन के विस्तार, रिक्त पदों को भरने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग सरकार से की है।

कांग्रेस नेताओं को अच्छे डॉक्टर से आंखों की जांच करवाकर चश्मा लगवाना चाहिए: लखनपाल

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित विशाल आक्रोश रैली के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अच्छे डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करवाकर चश्मा लगवा लेना चाहिए, तब उन्हें बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विकास की वास्तविक तस्वीर दिखाई देगी।

विधायक ने कहा कि भाजपा की आक्रोश रैली किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक आंदोलन था, जिसमें दोनों मंडलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों, प्रशासनिक दुरुपयोग और क्षेत्र की समस्याओं के विरोध में आयोजित किया गया था। विधायक लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाखड़ा पेयजल योजना की परिकल्पना और प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। प्रारंभ में योजना ब्यास नदी से प्रस्तावित थी, लेकिन तकनीकी कारणों से बाद में इसे भाखड़ा बांध से जोड़ा गया तथा इसके टेंडर भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही किए गए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बनने के बाद योजना की गति धीमी पड़ गई और आज भी कार्य अधूरा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि दिसंबर तक योजना शुरू होने का दावा किया जा रहा है तो उसकी वास्तविक प्रगति और शेष कार्यों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त जल भंडारण टैंकों की आवश्यकता है, वहां पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए। विधायक ने कहा कि जल शक्ति विभाग में हुई नियुक्तियों को लेकर उन्हें अनेक युवाओं की शिकायतें मिली हैं।

नव प्रवेशित छात्रों को झंडूता कॉलेज की व्यवस्था और गतिविधियों की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय झंडूता में नए शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एकदिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था, नियमों, अनुशासन और सह-शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत करवाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय कुमार ने किया। वरिष्ठ विद्यार्थियों ने नवागंतुकों का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को कॉलेज की कार्यप्रणाली, आंतरिक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी। कॉलेज प्रशासन ने एंटी-रैगिंग नियमों की जानकारी देते हुए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों को एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स एंड रेंजर्स, खेल गतिविधियों और रेड रिबन क्लब जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

संविदा कर्मचारियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ (एचजीसीटीए) ने संविदा कर्मचारियों से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने का स्वागत किया है। संघ ने इसे प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों की ऐतिहासिक जीत बताया है। एचजीसीटीए की प्रदेशाध्यक्ष बनिता सकलानी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि संविदा सेवा अवधि को कर्मचारियों के सेवा लाभों से अलग नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि संविदा सेवा की गणना वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के माध्यम से न्यायालयों के फैसलों को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया, जिसे उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। एचजीसीटीए के अनुसार, इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। संघ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय भार कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों से इनकार का आधार नहीं हो सकता। बनिता ने मांग की कि सरकार अब बिना देरी के सभी पात्र कर्मचारियों को संविदा सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति व अन्य लाभ प्रदान करे, अब सरकार को न्यायालय के आदेशों का निष्पक्ष और तत्काल पालन करना चाहिए।

विस्तार विधायक सुरेश कुमार ने बस्सी में व्यावसायिक केंद्र का किया शिलान्यास, कहा-

भोरंज में करवाए जा रहे करोड़ों के विकास कार्य

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। विधायक सुरेश कुमार ने बुधवार को बस्सी चौक पर लगभग 3.65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले व्यावसायिक केंद्र के पहले ब्लॉक एवं पार्किंग का शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार ने बताया कि इस व्यावसायिक केंद्र के पहले ब्लॉक पर लगभग साढे 95 लाख रुपए खर्च होंगे।

व्यावसायिक केंद्र के दोमंज़िला परिसर में करीब 115 आधुनिक दुकानें बनाई जाएंगी, जिनमें स्थानीय दुकानदारों और युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद उपमंडल मुख्यालय भोरंज का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। यहां रिंग रोड, खेल मैदान, रेन शैल्टरों और शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ बस्सी चौक से भकरेड़ी चौक और तरक्वाड़ी चौक तक तथा आस-पास के क्षेत्रों में सोलर लाइटें भी लगाई जाएंगी। यहां युवाओं को लाइब्रेरी और कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। आने वाले समय में इन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सुरेश कुमार ने बताया कि भोरंज में बीडीओ के कार्यालय भवन के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यहां न्यायिक परिसर का कार्य भी जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा। बस्सी के अस्पताल की कायाकल्प की गई और अब यहां कुल 12 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। अल्ट्रासाउंड और अत्याधुनिक एक्सरे मशीन का प्रावधान किया गया है। यहीं पर 24.50 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए ब्यास नदी से 45 करोड़ रुपए की योजना का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है।

बलोखर से मुंडखर तक के क्षेत्र के लिए गोविंदसागर झील से 93 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। जाहू में औद्योगिक क्षेत्र और एक बड़ा मैदान विकसित किया जा रहा है। भोरंज क्षेत्र की छूटी सभी बस्तियों को एंबुलैंस रोड से जोड़ा जा रहा है। पट्टा-अवाह देवी सड़क, बढार-कैहरवीं, भरेड़ी-कांगू और टिक्कर-मनोह सड़क सहित क्षेत्र की सभी मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण के लिए बजट आवंटित किया गया है।

इस अवसर पर कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया और स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले, एसडीएम शशिपाल शर्मा ने विधायक का स्वागत किया तथा व्यावसायिक केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी विधायक का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल, बीडीसी अध्यक्ष पूनम कुमारी, एएसपी लालमन शर्मा, तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, नगर पंचायत के सचिव पंकज कुमार, जेई संजय पठानिया, विजय डोगरा, दीप चंद, पवन कौशल, कर्म चंद, कांग्रेस के अन्य नेता, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

अवैध माइनिंग के टिप्पर चालक की दबंगई, पुलिस टीम पर चढ़ाने का प्रयास और एएसआई से हाथापाई

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में अवैध माइनिंग मटीरियल ले जा रहे एक टिप्पर चालक ने पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया और पीछा करने पर सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा काबू किए जाने के दौरान आरोपी ने एएसआई से हाथापाई कर उसकी वर्दी फाड़ दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस ने टिप्पर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, माइनिंग विभाग ने लदपालवां टोल प्लाजा के पास हिमाचल प्रदेश से बिना बिल के अवैध रूप से रेत-बजरी लेकर पंजाब आ रहे कुछ टिप्परों को पकड़ा था। इन वाहनों की निगरानी के लिए पुलिस टीम तैनात की गई थी। एएसआई दिलीप सिंह और एएसआई रणवीर सिंह की ड्यूटी सरकारी ईआरवी वाहन पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। पुलिस शिकायत के मुताबिक, तड़के करीब 4:10 बजे बिना नंबर

▶ पुलिस नाके से टिप्पर भगाने वाले चालक पर केस दर्ज, जानलेवा हमले सरकारी काम में बाधा का आरोप

वाले एक टिप्पर चालक ने अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन स्टार्ट कर दिया।

पुलिसकर्मियों ने टॉर्च दिखाकर और आवाज लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिसकर्मियों पर टिप्पर चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस टीम ने ईआरवी वाहन से टिप्पर का पीछा किया। अड्डा परमानंद के पास पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने तेज रफ्तार से सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी ने एएसआई दिलीप सिंह के साथ धक्का-मुक्की की और उनकी वर्दी फाड़ दी। बाद में वह अपना टिप्पर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला, सरकारी ड्यूटी में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज कर

न्यूज शॉर्ट्स

रुड़की का दुष्कर्म मामलाः दोषी सुहैल को 21 साल की कठोर सजा

भारतेंदु संवाददाता, रुड़की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 21 साल की सश्रम सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। बच्ची को दो लाख की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 सितंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी को गांव के ही एक युवक सुहैल उर्फ राणा ने दूध लाने के लिए कहा। उसकी बेटी दूध लेकर जब आरोपीत के घर पर पहुंची तो उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश, प्रेमी निकला प्रेमिका का कातिल

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। घर से लापता युवती की गुमशुदगी आखिरकार एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गई। प्रेम प्रसंग में उपजे विवाद के बाद आरोपी ने कथित तौर पर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान मिटाने की नीयत से शव गंगनहर में फेंक दिया। वाट्सएप काल पर स्वजन को हत्या की धमकी देने वाले आरोपित को बहादराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनते भाखड़ा नाले में बाइक समेत बहे 2 ग्रामीण

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। तेज बारिश के बाद उफान पर आए फतेहपुर रेंज स्थित भाखड़ा नाले को पार करने की कोशिश में बाइक सवार दो ग्रामीण तेज बहाव में 30 मीटर तक बहने के बाद फंस गए। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर पानी का स्तर कम होने से दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए और बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मंगलवार सुबह दो ग्रामीण हल्द्वानी से कालाढूंगी की ओर बाइक से जा रहे थे। फतेहपुर के पास भाखड़ा नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। बहाव का सही अंदाजा न होने पर उन्होंने बाइक सहित नाला पार करने का प्रयास किया। बीच नाले में पहुंचते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक बाइक समेत तेज बहाव में बहने लगे।

प्रतापनगर पोक्सो केस में मिली सफलता, मुख्य आरोपित दिवाकर डिमरी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, टिहरी। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित दिवाकर डिमरी को लंबगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश था। पीड़िता की मां ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को हिरासत में लिया। मामले में जांच जारी है।

परंपरा और पर्यावरण संरक्षण से ही सुरक्षित होगा भविष्य :स्वामी चिदानन्द सरस्वती

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परमार्थ निकेतन में बुधवार को गुरु पूजन एवं पादुका पूजन समारोह श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर परमार्थ पीठाधीश्वर स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने देशवासियों और विश्वभर के श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए परंपराओं के संरक्षण के साथ पर्यावरण बचाने का आह्वान किया।

प्रेम विवाह पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत

वयस्क युवती की सहमति से हुए विवाह को माना वैध, हाईकोर्ट ने अपहरण का मुकदमा किया रद

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रेम विवाह करने वाले एक वयस्क जोड़े को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही अपहरण की कानूनी कार्रवाई को रद कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वयस्क महिला अपनी इच्छा और सहमति से विवाह करती है तो उसे अपहरण का मामला नहीं माना जा सकता। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ विवाह करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

मामला हरिद्वार जिले के रुड़की निवासी शीतल सिंह और पिंकी से जुड़ा है। दोनों ने 23 मार्च 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था और 30 अप्रैल 2015 को अपने विवाह का विधिवत पंजीकरण भी करा लिया था। इसके बावजूद युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब उनकी बेटी बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा देने जा रही थी, उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया।

◆ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर मिली राहत

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवती बालिग थी और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह किया था। दोनों का विवाह कानूनी रूप से संपन्न होने के साथ ही उसका पंजीकरण भी कराया जा चुका था। ऐसे में अपहरण का आरोप प्रथम दृष्टया टिकता नहीं था।

हाईकोर्ट ने अपहरण की कानूनी कार्रवाई की समाप्त

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वयस्क महिला अपनी इच्छा और सहमति से विवाह करती है तो उसे अपहरण का मामला नहीं माना जा सकता। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ विवाह करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

हाईकोर्ट का अहम निर्णय ?

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केवल परिवार की असहमति या माता-पिता की नाराजगी के कारण किसी वयस्क महिला द्वारा किए गए विवाह को अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है और विवाह करती है तो ऐसे मामलों में अपहरण की धाराओं का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवनसाथी चुनने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। इस फैसले को ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है, जहां प्रेम विवाह करने वाले वयस्क जोड़ों के खिलाफ परिवार की आपत्ति के बाद अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज करा दिए जाते हैं।

आपदा राहत में न हो देरी, गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और वर्षा से अवरुद्ध मोटर मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र खोला जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज हों और बंद सड़कें जल्द खुलें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गढ़वाल आयुक्त ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानसून और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी परिसंपत्तियों की क्षति का तत्काल आकलन किया जाए। उन्होंने जनहानि एवं पशुहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अहैतुक सहायता राशि समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

◆ प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सहायता देने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नदी-नालों और गाड़-गदेरों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए जल निकासी व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया। आयुक्त ने कहा कि किसी भी दैवीय आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को आपदा राहत मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि के लिए तत्काल शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।

सभी जनपदों को आपदा राहत धनराशि मिली

चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान आनंद स्वरूप ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग की भारी वर्षा संबंधी चेतावनी के मद्देनजर प्रतिकूल परिस्थितियों में यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से रोकने तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित पड़ावों पर ठहराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और स्थानीय संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि किसी भी दैवीय आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को आपदा राहत मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि के लिए तत्काल शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।

चट्टान दरकने से बंद हुआ कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग, 20 गांवों का टूटा संपर्क

कैलास मानसरोवर मार्ग और मुनस्यारी-मिलम सड़क बंद, एक लाख आबादी प्रभावित

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है। धारचूला से लगभग 54 किलोमीटर दूर नज्यांग के पास चट्टानें दरकने से तवाघाट-लिपुलेख यानी कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। मार्ग बंद होने से कई वाहन रास्ते में फंस गए और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है तथा मार्ग खोलने के लिए मशीनें लगाकर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बारिश का असर केवल कैलास मानसरोवर मार्ग तक सीमित नहीं है। चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मुनस्यारी-मिलम मार्ग भी बोगडियार के पास लगातार दूसरे दिन बंद रहा। इसके अलावा जिले की 16 ग्रामीण सड़कें भी भूस्खलन और मलबा आने के कारण अवरुद्ध हैं। सड़क संपर्क टूटने से करीब 20 उच्च हिमालयी गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में सड़कें बंद होने से एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए संबंधित विभागों की टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं। अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

उच्च हिमालयी क्षेत्र का टूटा संपर्क

चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मुनस्यारी-मिलम मार्ग भी बोगडियार के पास लगातार दूसरे दिन बंद रहा। इसके अलावा जिले की 16 ग्रामीण सड़कें भी भूस्खलन और मलबा आने के कारण अवरुद्ध हैं। सड़क संपर्क टूटने से करीब 20 उच्च हिमालयी गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है।

कॉर्बेट बना बाघ संरक्षण का गढ़

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ संरक्षण में देश का सिरमौर बना उत्तराखंड

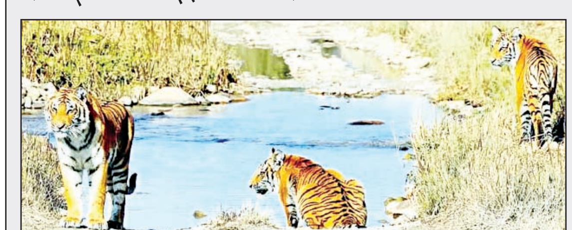

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश में बाघ संरक्षण की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। अपनी जैव विविधता, बेहतर प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों के कारण कॉर्बेट में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यहां करीब 260 बाघ मौजूद हैं, जो इसे देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में सबसे आगे खड़ा करते हैं। वर्ष 2006 में कॉर्बेट में लगभग 150 बाघ दर्ज किए गए थे। इसके बाद संरक्षण कार्यों के चलते वर्ष 2010 में यह संख्या 184, 2014 में 215, 2018 में 231 और 2022 में 260 तक पहुंच गई। बाघों की बढ़ती संख्या उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है।

देवभूमि हरिद्वार में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवभूमि हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। गंगा तट से लेकर प्रमुख अखाड़ों और आश्रमों तक दिनभर धार्मिक आयोजन हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने संतों का पूजन कर आशीर्वाद लिया और गुरु दीक्षा ग्रहण की। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। देश विदेश से पधारे अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का दिन है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सेतु है। आज का युवा यदि गुरु के बताए मार्ग पर चले तो समाज में संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना स्वतः विकसित होगी।

चमोली की फूलों की घाटी की मनमोहक छटा अब पोस्टकार्ड पर

भारतेंदु संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की प्राकृतिक सुंदरता अब विशेष चित्रित पोस्टकार्ड के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचेगी। ज्योतिर्मठ डाक विभाग ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर आधारित पोस्टकार्ड जारी किया है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने इसका विमोचन किया। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड की प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी को अब एक नए माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

कालाढूंगी में विकसित भारत और नशा मुक्ति अभियान संपन्न

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय संचार ब्यूरो, नैनीताल द्वारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, कालाढूंगी में आयोजित दो दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, ग्रामीण अभियान तथा नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। चित्र प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

◆ कालाढूंगी में चित्र प्रदर्शनी संग जागरूकता अभियान हुआ संपन्न

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों से बचने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने युवाओं को सरकारी योजनाओं से जुड़ने और स्वस्थ समाज निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू रक्षा दल सक्रिय

कांवड़ यात्रा में मांस-शराब बिक्री पर रोक की मांग

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून में हिंदू रक्षा दल ने जिला प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। संगठन ने कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रशासन द्वारा चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा अवधि के दौरान मांस और शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर संचालित होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिष्ठान का नाम तथा लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की भी मांग की गई है।

हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों की ओर जाते हैं। ऐसे में यात्रा मार्गों पर शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

हिंदू रक्षा दल ने प्रशासन से सख्त प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।

संगठन ने मांग की कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही श्रद्धालुओं को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट पहचान होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। संगठन ने प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है। अब इन मांगों पर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

ऋषिकेश में गुरु पर्व पर डॉ. अग्रवाल ने संतों के चरणों में अर्पित की श्रद्धा

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। गुरु पर्व के पावन अवसर पर ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न आश्रमों में पहुंचकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने जयराम आश्रम में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी से भेंट कर गुरु परंपरा की महिमा का उल्लेख किया। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान करते हैं। इसके बाद उन्होंने माया कुंड स्थित डंडीवाड़ा आश्रम पहुंचकर पूज्य केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद लिया।

◆ आश्रम में गुरुजनों का सम्मान, डॉ. अग्रवाल ने बताए गुरु के महत्व

उन्होंने कहा कि गुरुजन समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति तथा जनकल्याण की कामना की।

कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए फार्मेसी भवन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कुमाऊं विश्वविद्यालय के भीमताल परिसर में नवनिर्मित सीडीएस जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का बुधवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। कुलाधिपति एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर इस भवन का नामकरण बेहद प्रेरणादायक है। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने कहा कि छात्र अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के विकास में करें। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल साइंसेज विभाग की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि नया अकादमिक ब्लॉक शोध, नवाचार और कौशल विकास को नई दिशा देगा।

उन्होंने बताया कि यह भवन भारत सरकार की पीएम-उषा योजना के तहत निर्मित किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और शोध आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड औषधीय और सुगंधित पौधों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जहां फार्मेसी क्षेत्र में अनुसंधान की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

आपदा | नैनी झील का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क, भारी बारिश को लेकर जारी ऑरेंज अलर्ट जारी

लगातार मूसलाधार बारिश से नैनी झील का जलस्तर 84 फीट पहुंचा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। सरोवर नगरी नैनीताल में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। मंगलवार तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश और पूरे दिन छाए घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट का असर सुबह तीन बजे से ही दिखाई देने लगा, जब तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग तीन घंटे तक लगातार जारी रहा। लगातार वर्षा के कारण नैनी झील का जलस्तर बढ़कर 84 फीट तक पहुंच गया, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है।

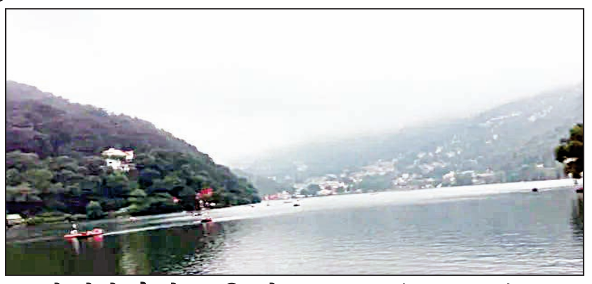

नैनीताल का मौसम पूरे दिन बदलता रहा। सुबह से लेकर शाम तक शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। हल्की रिमझिम बारिश के बीच दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम करीब चार बजे के बाद ही कोहरा कुछ हद तक छंटा और लोगों को राहत मिली। हालांकि इसके बाद भी बीच-बीच में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में लगभग 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई।

◆ घने कोहरे और तेज बारिश से नैनीताल बेहाल, डीएम ने सभी विभागों को किया सतर्क

तेज बारिश के कारण शहर के नाले उफान पर आ गए। सात नंबर क्षेत्र के कुछ घरों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की आशंका भी बढ़ गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

प्रशासन ने की लोगों से अपील

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर पालिका, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमों को संभावित संकट से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां कहीं भी मलबा या पेड़ गिरने की सूचना मिले, वहां तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी और नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। नैनी झील का जलस्तर लगातार बढ़ने पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। झील से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और संबंधित विभाग नियमित रूप से जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो झील का जलस्तर और बढ़ सकता है।

पर्यटकों को चेतावनी

पर्यटन नगरी होने के कारण नैनीताल में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक भी मौजूद हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लेने, झील किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाने तथा सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

मोहाली में विकास भवन पहुंचकर मनरेगा कर्मियों ने दिया धरना

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मोहाली। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोहाली स्थित विकास भवन के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की।

मनरेगा कर्मचारियों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जब प्रदर्शनकारी कर्मचारी विकास भवन के अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने भवन के दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए। इसके बाद कर्मचारियों ने गेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी की। बाद में यूनियन नेताओं ने गेट पर खड़े होकर कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल रहीं।

मनरेगा कर्मचारी यूनियन पंजाब के नेताओं ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कठिन और असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम का अधिक दबाव, कम वेतन, वेतन में असमानता और नौकरी की अनिश्चितता के कारण कर्मचारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

यूनियन प्रधान गुरसेवक सिंह ने कहा कि राज्य के अलग-अलग जिलों में मनरेगा कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असमानता की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने मांग की कि पूरे पंजाब में एक समान वेतन नीति और कॉमन सर्विस रूल्स तुरंत लागू किए जाएं।

कर्मचारियों ने यह भी मांग की कि मनरेगा स्टाफ को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में मर्ज कर नियमित करने की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही पे स्केल, पे प्रोटेक्शन और पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू करने की मांग भी उठाई गई।

यूनियन नेताओं ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 58 वर्ष की आयु तक या योजना लागू रहने तक सुरक्षित किया जाना चाहिए।

पंजाब में चुनावी मिशन पर उतरेंगे भूपेश बघेल

10 दिन के दौरे में विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से संवाद और 2027 चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल 30 अगस्त से 10 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी संगठन की स्थिति का आकलन करेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व इस दौरे को आगामी चुनावों की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। पार्टी का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है।

दौरे के पहले चरण में भूपेश बघेल 30 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वे अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। इन बैठकों में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के प्रधान, हलका अध्यक्ष, मंडल प्रधान तथा ब्लॉक समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन के हर स्तर से जुड़े पदाधिकारी इन बैठकों में भाग लेकर अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और चुनौतियों से अवगत कराएं।

बैठकों का मुख्य उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना होगा। इसके तहत विधानसभा क्षेत्रवार संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, चुनाव प्रचार की रूपरेखा, स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों तथा जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं के सुझावों को भी गंभीरता से सुनेगा ताकि चुनावी रणनीति को जमीनी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके। इसके

अलावा यह भी समीक्षा की जाएगी कि किन क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है तथा किन मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकती है।

पंजाब कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव कैप्टन संदीप संधू ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को पत्र जारी कर बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भूपेश बघेल के साथ होने वाली बैठकों में सभी आमंत्रित पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पार्टी का मानना है कि चुनावी तैयारियों को सफल बनाने के लिए संगठन के प्रत्येक स्तर की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

यह पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले भी वह छह दिनों तक चंडीगढ़ में रहकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न गुटों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। उन बैठकों में उन्होंने संगठन की कार्यप्रणाली, कार्यकर्ताओं की समस्याओं, राजनीतिक हालात और पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी पर विस्तृत चर्चा की थी। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और चुनाव समितियों में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं मानी थी।

गौरतलब है कि पिछले कई महीनों तक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों के बीच गुटबाजी की चर्चाएं होती रही हैं।

न्यूज ब्रीफ

गमाडा पर अदालत सख्त, कुर्की के आदेश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। स्थायी लोक अदालत ने गमाडा के संपदा अधिकारी के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर की गई है। अदालत ने गमाडा कार्यालय के फर्नीचर और सरकारी वाहन को कुर्क करने का निर्देश दिया है। मामला एयरोसिटी में प्लॉट खरीदने वाले व्यक्ति से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि गमाडा ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं। स्थायी लोक अदालत ने वर्ष 2024 में गमाडा को एक लाख रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया था। भुगतान नहीं होने पर अदालत ने कुर्की के आदेश जारी किए।

फर्जी बिल घोटाले में पूर्व एक्सईएन को जेल

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। सीबीआई की विशेष अदालत ने 1.62 करोड़ रुपये के फर्जी रनिंग बिल घोटाले में पंजाब लोक निर्माण विभाग के पूर्व एक्सईएन जोगिंदर सिंह को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। मामला वर्ष 2011 का है, जब बठिंडा विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों से जुड़ा फर्जी बिल तैयार कर सरकारी धन जारी करवाया गया था। जांच में सामने आया कि बिल पर एसडीई और जेई के जाली हस्ताक्षर किए गए थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए, जिनके बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित हुआ।

नयागांव जल संकट पर प्रदर्शन, पार्षद हिरासत में

भारतेन्दु संवाददाता, नयागांव। पेयजल संकट को लेकर बुधवार को इलाके के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्षद रवि बिष्ट को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इसके विरोध में लोगों ने नगर परिषद परिसर में धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। लोगों ने जल्द पेयजल व्यवस्था सुधारने और उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

मोहाली में कार चोर गिरोह का पर्दाफाश

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी गुरशरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की चार कारें बरामद की हैं। इनमें दो वर्ना, एक जेन और एक ऑल्टो शामिल हैं। आरोपी को अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह पुरानी कारें चोरी कर उनके पुर्जे बेचता था या पूरी कारों को बेच देता था। यह कार्रवाई सेक्टर-69 से चोरी हुई वर्ना कार की जांच के दौरान हुई। डीएसपी हरसिमरत सिंह बल ने बताया कि अर्शदीप सिंह और गिल नामक दो अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

फेज-5 में 11 घंटे बिजली गुल, लोग परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। फेज-5 में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को करीब 11 घंटे तक बिजली संकट झेलना पड़ा। फ्यूज खराब होने से हाउस नंबर-1616 वाली गली और आसपास के कई घरों की बिजली आपूर्ति ठप रही। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय पर समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों से संपर्क भी नहीं हो पाया। भीषण गर्मी में बिजली बंद रहने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मामूली खराबी ठीक करने में इतना समय लगना बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से लापरवाही दूर करने और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न होने की अपील की है।

मौसम बदलाव से बच्चों में बढ़ा वायरल संक्रमण, अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी भीड़

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बच्चों में मौसमी बुखार और वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिविल अस्पताल फेज-6 की बाल रोग ओपीडी में रोजाना 35 से 40 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें नवजात शिशु और पांच वर्ष तक के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डॉक्टरों के अनुसार, तेज धूप और बारिश के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे वायरल संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों में तेज बुखार, सर्दी, खांसी, गले में संक्रमण और कमजोरी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं।

बाल रोग विशेषज्ञ साहिल विकास ने बताया कि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए वे संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की सेहत का ध्यान रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है।

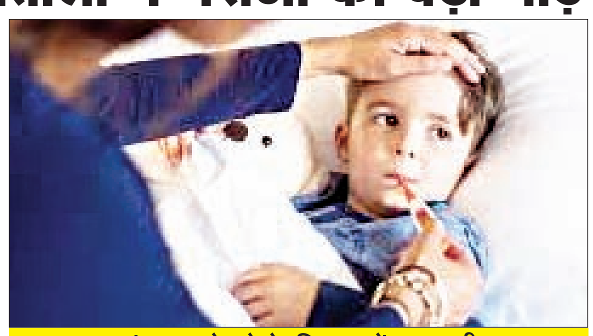

संक्रमण रोकने के लिए बरतें सावधानी

मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों को बदलते मौसम में ठंडी हवा, बारिश में भीगने और अचानक तापमान परिवर्तन से बचाना चाहिए। बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं और उनके शरीर को गर्म रखने का ध्यान रखें। बच्चों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उन्हें नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। बच्चों को संक्रमित लोगों से दूरी रखने की सलाह दें, ताकि वायरस फैलने का खतरा कम हो सके। छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के आसपास साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके खिलौने, बोतल और इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को नियमित रूप से साफ करें। बच्चों को पौष्टिक आहार दें, जिसमें फल, सब्जियां, दूध और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल हो, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे।

ज्योति मौत मामले में पीयू देगा 21 लाख मुआवजा और भाई को नौकरी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर ज्योति की मौत के मामले में बुधवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और मृतका के परिजनों के बीच सहमति बन गई। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद प्रशासन ने परिवार को 21 लाख रुपये का मुआवजा देने और ज्योति के छोटे भाई को नौकरी देने की घोषणा की। इसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए।

समझौते के बाद ज्योति के शव का डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव लेकर जाएगा। इससे पहले परिजन और विभिन्न छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे थे।

परिजनों की प्रमुख मांगों में हादसे की जिम्मेदारी तय करना, परिवार को आर्थिक सहायता देना और एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराना शामिल था। उनका आरोप था कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकी।

गौरतलब है कि मंगलवार सुबह पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल नंबर-8 और 10 के बीच स्थित क्षेत्र में ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

घटना के बाद पुलिस, बिजली विभाग और पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का उद्देश्य हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाना और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय करना है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुआवजे और नौकरी की घोषणा के बाद फिलहाल मामला शांत हुआ है। हालांकि, छात्रों और परिजनों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग जारी है।

अमृतपाल की रिहाई की मांग पर वारिस पंजाब दे के समर्थकों का चंडीगढ़ कूच

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

बंदी सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के समर्थकों ने बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकारी रिहायश का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मोहाली-चंडीगढ़ सीमा सहित कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर समर्थकों को रोकने की व्यवस्था की गई थी।

प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने भारी संख्या में जवानों की तैनाती की थी। पुलिस ने पहले ही सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ आमने-सामने आ गए।

मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटा दिए और आगे बढ़ने की

कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसका भी सामना करते हुए पानी की बौछारों को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर चंडीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता मनप्रीत अयाली ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग बंदी सिंहों और सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई है।

मनप्रीत अयाली ने कहा कि सरकार को बंदी सिखों से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनकी रिहाई को लेकर उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से बंदी सिंहों की रिहाई की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी मांग को लेकर समर्थकों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का फैसला किया था।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। चंडीगढ़ और मोहाली के प्रमुख रास्तों पर निगरानी रखी गई। अधिकारियों का प्रयास रहा कि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो।

फिलहाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति को संभालने के प्रयास जारी रहे। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं।

मोहाली में यातायात नियम तोड़ने वालों पर आरटीए की सख्ती

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

◆ मोहाली में यातायात अभियान, 1,903 चालान से वसूले 1.36 करोड़ रुपए

साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के खिलाफ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। मई 2026 से अब तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत 1,903 चालान किए गए हैं। इन चालानों से राज्य के खजाने में 1,36,63,501 रुपये की राशि जमा हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान निजी बसों की गलत पार्किंग और यातायात बाधित होने संबंधी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हरप्रीत सिंह अटवाल और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) गगनदीप सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान निजी बसों, पर्यटक बसों, स्कूल बसों और टैक्सियों की जांच की गई।

जांच के दौरान गलत पार्किंग, ओवरलोडिंग, सड़क कर से जुड़े नियमों के उल्लंघन, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आरटीओ हरप्रीत सिंह अटवाल ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन केवल व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से खड़े वाहन, क्षमता से अधिक भार ले जाने वाले वाहन और दस्तावेजों की कमी वाले वाहन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

उन्होंने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की कि वे सभी यातायात नियमों का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज हमेशा साथ रखें।

चंडीगढ़ में रेंट एग्रीमेंट अब होगा पूरी तरह ऑनलाइन

प्रशासन जल्द लॉन्च करेगा टेनेंसी पोर्टल, ऑनलाइन पंजीकरण, यूआईएन, किराया संशोधन और शिकायत निस्तारण की मिलेगी सुविधा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कोर्ट या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही एक नया टेनेंसी पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से किरायेदारी से जुड़ी अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाना है।

मंगलवार को जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने प्रस्तावित पोर्टल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल आम लोगों के लिए सरल, सुरक्षित और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली होना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों के अनुसार, नागरिक ह्यद्गह्न1द्बष्द्गश्ठ्ठद्यद्बठ्ठद्ग.द्दश1.द्बठ्ठ के माध्यम से किरायेदारी समझौते का ऑनलाइन पंजीकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) प्राप्त करना, किराया संशोधन के लिए आवेदन करना तथा शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

प्रशासन ने चंडीगढ़ टेनेंसी रूल्स-2026 का मसौदा भी सार्वजनिक कर दिया है और इस पर आम जनता, मकान मालिकों, किरायेदारों तथा अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सुझाव एस्टेट ऑफिस में जमा कराए जा सकते हैं। ये नियम असम टेनेंसी एक्ट-2021 की धारा 44 के तहत तैयार किए गए हैं, जिसे चंडीगढ़ में लागू किया गया है।

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक किरायेदारी समझौते की जानकारी दो महीने के भीतर ऑनलाइन तहसीलदार को देना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के सात दिनों के भीतर संबंधित पक्षों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे किरायेदारी का कानूनी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पोर्टल पर उपलब्ध पूरा सिस्टम स्थानीय भाषा में भी होगा और सभी आवेदनों के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य रहेगा, जिससे फर्जी पंजीकरण पर रोक लग सके।

चंडीगढ़ में डिजिटल होगी किरायेदारी व्यवस्था

चंडीगढ़ में मकान मालिकों और किरायेदारों को जल्द बड़ी सुविधा मिलने वाली है। प्रशासन एक नया टेनेंसी पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण और अन्य किरायेदारी संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पोर्टल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे सरल, सुरक्षित और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एनआईसी के अनुसार, नागरिक पोर्टल पर किरायेदारी समझौते का पंजीकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) प्राप्त करना, किराया संशोधन के लिए आवेदन और शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण कर सकेंगे। प्रशासन ने चंडीगढ़ टेनेंसी रूल्स-2026 का मसौदा भी जारी कर दिया है और इस पर 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। नए नियमों के अनुसार, हर किरायेदारी समझौते की जानकारी दो महीने के भीतर ऑनलाइन दर्ज कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के सात दिनों के भीतर यूआईएन जारी किया जाएगा।

नयागांव में जलभराव से परेशान लोगों ने मांगा स्थायी समाधान

भारतेन्दु संवाददाता, नयागांव

लगातार हो रही बारिश के कारण नयागांव क्षेत्र में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। कई गलियां और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती पानी की उचित निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण जगह-जगह पानी जमा हो गया है और लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, क्षेत्र में बनी अधिकांश स्टॉर्म वाटर पाइप लाइनें लंबे समय से ब्लॉकेज का शिकार हैं। बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं हो पाने के कारण सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के समय यही समस्या सामने आती है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है।

जलभराव के कारण पैदल चलने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई जगहों पर सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई घरों के बाहर तक गंदा पानी पहुंच गया है, जिससे संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात से पहले ही नालियों और स्टॉर्म वाटर पाइप लाइनों की सफाई करवा दी जानी चाहिए थी, ताकि बारिश के समय लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और पाइपलाइन की सफाई का काम जल्द पूरा करने की अपील की है।

निवासियों का कहना है कि नयागांव में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति पैदा होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल अस्थायी समाधान किए जाते हैं। लोगों ने मांग की है कि इस समस्या के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी जमा न हो।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर राहत पहुंचाने की अपील की है। उनका कहना है कि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

संशोधित बेअदबी विधेयक पर अकाल तख्त करेगा समीक्षा

पंजाब सरकार ने संशोधित बेअदबी कानून का मसौदा सौंपा, अकाल तख्त पांच सिंह साहिबानों की बैठक में करेगा विचार

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर

बेअदबी कानून में संशोधन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब सरकार ने बुधवार को अपना संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में जमा करवा दिया। सरकार की ओर से 25 पन्नों का संशोधित कानून का प्रारूप और उठाई गई आपत्तियों के जवाब आधिकारिक रूप से सौंपे गए हैं। इस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से सिख संगठनों और सरकार के बीच चर्चा चल रही थी।

पंजाब सरकार की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने यह दस्तावेज श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के प्रभारी को सौंपे। यह कदम उस समय उठाया गया जब श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने बेअदबी कानून में मौजूद आपत्तिजनक प्रावधानों और शब्दावली में बदलाव के लिए पंजाब सरकार को एक महीने का समय दिया था।

बुधवार को इस अवधि का अंतिम दिन था। सरकार ने समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना

संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब को सौंप दिया। दस्तावेज जमा करवाने के बाद विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर ने कहा कि पंजाब सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी कि संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना पक्ष आधिकारिक रूप से रख दिया है।

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या नए मसौदे में सिख समुदाय की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब आगे का निर्णय श्री अकाल तख्त साहिब को करना है और धार्मिक संस्था की राय के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी।

वहीं, श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से प्रतिनिधि जसकरण सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सौंपे गए संशोधित मसौदे का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे खालसा पंथ की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पांच सिंह साहिबानों की आगामी बैठक में इस मसौदे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कानून के प्रत्येक पहलू और उसमें किए गए संशोधनों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब अपनी आधिकारिक राय पंजाब सरकार को देगा।

जसकरण सिंह ने यह भी कहा कि सरकार को मसौदा तैयार करने से पहले श्री अकाल तख्त साहिब के साथ औपचारिक बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में विद्वानों और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई जानी चाहिए, ताकि ऐसा कानून तैयार हो सके जो सिख भावनाओं के अनुरूप होने के साथ-साथ सभी पक्षों को स्वीकार्य हो।

श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि 3 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधित बेअदबी विधेयक को तब तक पेश न किया जाए, जब तक कि श्री अकाल तख्त साहिब मसौदे की समीक्षा पूरी कर अपनी राय सरकार को नहीं दे देता।

इस पूरे मामले को लेकर अब सबकी नजरें पांच सिंह साहिबानों की बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि बैठक में संशोधित मसौदे की हर धारा पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कानून को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा या इसमें और बदलाव किए जाएंगे।

बेअदबी कानून संशोधन का मामला धार्मिक भावनाओं और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण पंजाब में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

सफाई कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का ठुकराया पैकेज

सरकार के फैसले से असंतुष्ट कर्मचारी, वेतन और नियमितीकरण की मांग पर अड़े

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से सफाई सेवकों और सीवरमैन के लिए घोषित किए गए कल्याणकारी पैकेज को सफाई कर्मचारी यूनियन ने खारिज कर दिया है। यूनियन ने कहा है कि सरकार की घोषणा से उनकी प्रमुख मांगों का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए राज्यभर में चल रही हड़ताल जारी रहेगी।

यूनियन नेताओं ने सरकार द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 अगस्त से बढ़ाकर 20,520 रुपये किए जाने के फैसले पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विभिन्न कटौतियों के बाद कर्मचारियों के हाथ में करीब 16 हजार रुपये ही बचेंगे, जबकि उनकी मांग न्यूनतम 40 हजार रुपये मासिक वेतन की है।

सफाई कर्मचारी यूनियन के महासचिव गई चंद ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को यूनियन ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण और बेहतर सेवा शर्तें शामिल हैं। जब तक इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

यूनियन ने नियमितीकरण के लिए तय की गई 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा का भी विरोध किया है। यूनियन के राज्य सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि राज्य में करीब 30 हजार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। उन्होंने कहा कि इनमें कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें कुछ साल पहले ही संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था। इसलिए सरकार को आयु सीमा में राहत देनी चाहिए।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने मंगलवार देर रात सफाई सेवकों और सीवरमैन के लिए कल्याणकारी पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लाने, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों और वर्ष 2021 में नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था।

इसके अलावा सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाकर 20,520 रुपये करने की घोषणा की थी। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे सफाई कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला बताया था। उन्होंने कहा था कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को पात्र कर्मचारियों का रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हालांकि, सफाई कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सरकार का पैकेज उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और अन्य मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सफाई कर्मचारी अपना आंदोलन और हड़ताल जारी रखेंगे।

सरकार और यूनियन के बीच विवाद के चलते राज्यभर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और कर्मचारियों के बीच आगे की बातचीत से कोई समाधान निकलता है या नहीं।

इस बीच प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं, यूनियन ने सरकार से जल्द बैठक बुलाकर मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है।

किसान परिवार की बेटी हरजिंदर कौर का कमाल, वेट लिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल

गांव मैहस की बेटी ने 227 किलो वजन उठाकर बढ़ाया देश का गौरव

भारतेंदु संवाददाता, पटियाला। नाभा के गांव मैहस की रहने वाली 30 वर्षीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता है। उन्होंने 69 किलो भार वर्ग में कुल 227 किलो वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने वर्षों के संघर्ष और मेहनत को भी सफलता में बदल दिया।

हरजिंदर कौर का सफर आसान नहीं रहा। खेतीबाड़ी से जुड़े परिवार में जन्मी हरजिंदर ने कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण हासिल किया। उनके पिता साहब सिंह गांव मैहस में खेती करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब परिवार के छह सदस्य दो कमरों के मकान में रहते थे। खेल उपकरण, प्रशिक्षण और पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी।

वेटलिफ्टिंग में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने से पहले हरजिंदर ने बचपन में घर के कामों के साथ मेहनत की। उन्होंने भैंसों के लिए चारा काटने वाली मशीनों पर घंटों काम किया। आज उन्हीं मेहनती हाथों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए दूसरा पदक हासिल किया है।

हरजिंदर कौर इससे पहले वर्ष 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। उस समय उन्होंने कुल 212 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। वह कबड्डी और रस्साकशी की राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।

उनके खेल करियर को नई दिशा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोच परमजीत शर्मा ने दी। रस्साकशी में उनकी प्रतिभा देखकर उन्होंने हरजिंदर को वेटलिफ्टिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2016 में वेटलिफ्टिंग शुरू की और लगातार मेहनत करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

हरजिंदर के लिए यह सफर चुनौतियों से भरा रहा। शुरुआत में लोगों ने लड़की होने के कारण वेटलिफ्टिंग करने पर सवाल उठाए।

कनाडा भेजने के नाम पर दंपती से लाखों की ठगी

भारतेंदु संवाददाता, नवांशहर। कनाडा भेजने का झांसा देकर दंपति से 8.70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता जसपाल और उनकी पत्नी गितिका निवासी नवांशहर ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात एजेंट अशोक कुमार मंगला निवासी जगराओं से हुई थी।

दंपति ने बताया कि एजेंट ने उन्हें स्पाउज वीजा के माध्यम से कनाडा भेजने का भरोसा दिया और इसके लिए 35 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। एजेंट ने पहले डिग्री बनवाने के नाम पर 2.70 लाख रुपये लिए और बाद में 6 लाख रुपये और ले लिए। इसके बाद भी उनका वीजा नहीं लगा।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समय बीतने के बाद एजेंट ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और धमकियां देने लगा।

पंजाब के अबोहर शहर में चार स्कूलों को मिली बम की धमकी

धमकी मिलने के बाद खाली करवाए स्कूल, पुलिस ने संभाला मोर्चा

भारतेंदु संवाददाता, अबोहर। अबोहर शहर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दो निजी स्कूलों समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली। ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस और सिविल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और विद्यार्थियों को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

धमकी की सूचना मिलते ही अभिभावकों में भी चिंता फैल गई। कई अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए तुरंत स्कूल पहुंचे। वहीं, स्कूल प्रबंधन ने स्कूली वाहनों के माध्यम से भी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की।

पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सर्च टीमों को मौके पर बुलाया गया और स्कूल परिसर के हर हिस्से की गहन जांच की गई। पुलिस टीमों ने कक्षाओं,

अबोहर स्कूल धमकी मामले में साइबर सेल करेगा अज्ञात ईमेल की जांच

कार्यालयों और अन्य स्थानों की तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।

डीएसपी हरीश कुमार ने बताया कि डीएवी स्कूल और अंजम्शन कॉन्वेंट स्कूल समेत तीन-चार स्कूलों को सुबह करीब आठ बजे के बाद धमकी भरी ईमेल मिली थी। ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूलों को खाली करवाया और सुरक्षा जांच शुरू कर दी।

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल स्मिता शर्मा ने बताया कि सुबह करीब सवा आठ बजे स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से धमकी भरा संदेश आया था।

टायर फैक्टरी के प्रदूषण से परेशान ग्रामीण, कार्रवाई की मांग की तेज

भारतेंदु संवाददाता, खन्ना। इकोलाहा गांव के पास स्थित टायर जलाने वाली फैक्टरी को लेकर आसपास के ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि कई लोग त्वचा संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

समाजसेवी संतोख सिंह बेनीपाल, गांव निवासी रामचंद सिंह और रविंदर सिंह ने बताया कि फैक्टरी के खिलाफ पहले भी प्रशासन और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायतें दी जा चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2021 में हुई जांच के दौरान भी कई अनियमितताएं सामने आई थीं और अधिकारियों ने कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन

इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्रामीणों ने बताया कि 10 जुलाई 2026 को उन्होंने दोबारा एसडीएम खन्ना को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि, लोगों का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी न तो मौके पर निरीक्षण किया गया और न ही रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप, एफबीआई ने की तलाश तेज

एफबीआई ने ड्रग तस्करी आरोपों में अमृतपाल सिंह को किया वांटेड

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पअमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने एक और भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को वांटेड घोषित किया है। एफबीआई के अनुसार, 30 वर्षीय अमृतपाल सिंह पर ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़े होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप हैं।

एफबीआई ने जारी जानकारी में बताया कि अमृतपाल सिंह की लंबाई करीब 5 फुट 9 इंच और वजन लगभग 61 किलोग्राम है। एजेंसी के अनुसार, वह संगठित अपराध गतिविधियों से जुड़े एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा रहा है, जो कई देशों में सक्रिय है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का संचालन कनाडा के वैंकूवर से किया जाता था। यह गिरोह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क को बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसी प्रतिबंधित मादक पदार्थों की आपूर्ति करता था। एफबीआई का कहना है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है। पंजाब से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क पर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय और विदेशी जांच एजेंसियों की नजर बनी हुई है। भारत, कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

शहीद उधम सिंह दिवस पर पंजाब में अवकाश घोषित

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर 31 जुलाई को पूरे राज्य में गजटेड छुट्टी घोषित की है। इस दिन पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा बैंक और अन्य सरकारी संस्थानों में भी यह अवकाश लागू होगा।

शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस हर वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा दी थी। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के हिसार जिले में हुआ था। उधम सिंह को जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर और उसके सहयोगियों को गोली मारकर शहीदों को न्याय दिलाने का प्रयास किया था।

अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े

भारतेंदु संवाददाता, फिरोजपुर। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अमृतसर-कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन के दोनों दिशाओं में पांच-पांच अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 05735/05736 अपने मौजूदा कोच संयोजन, समय-सारिणी और निर्धारित ठहराव के अनुसार संचालित होगी। ट्रेन संख्या 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल 7 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:25 बजे अमृतसर से रवाना होगी और अगले दिन रात 11:45 बजे कटिहार पहुंचेगी।

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank
...the name you can BANK upon !

शाखा: तंजावुर शाखा (048200)
नं. 366/1, अब्राहम पंडिथार रोड,
तंजावुर-613001, फोन: 04362-235036
ईमेल:- bo0482@pnb.bank.in

प्रतिस्थापित सूचना

दिनांक **15.07.2026** को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उपरोक्त शाखा द्वारा नीचे दिए गए ऋणी को जारी की गई सूचना।

1. ऋणी: मैसर्स वी लेबोरेटरीज, सुबाथू रोड, गांव-कैलर पी.पी., सपरून तहसील, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173211
2. साझेदार/गारंटर: श्री जी. शानमुगवेल, पुत्र गोविंदासामी, 45D, नॉर्थ स्ट्रीट, ओराथानाडु तालुक, किलामंगलम, तंजावुर-614615
3. साझेदार/बंधककर्ता: श्री चिन्नादुरई रामामूर्ति, नं.19, कालीरायर स्ट्रीट, नंबिवयाल पोस्ट, करंबाकुडी तालुक, पुदुकोट्टई-614615

उपरोक्त सूचना आपको पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी, परंतु आपको प्राप्त नहीं हो सकी। अतः सूचना की विषय-वस्तु इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।आपने बैंक के पक्ष में संबंधित दस्तावेज निष्पादित कर कुल **रू. 83,08,000/- (रुपये तिरासी लाख आठ हजार मात्र)** की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। आपने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है और दिनांक **30/06/2026** तक **रू. 48,19,442.01/- (रुपये अड़तालीस लाख उन्नीस हजार चार सौ बयालीस रुपये एक पैसा मात्र)** की राशि ब्याज एवं अन्य लागतों सहित देय है, जिस पर आपके द्वारा सहमत दर से आगे ब्याज भी लगेगा। बैंक को देय या भविष्य में देय होने वाली राशि की प्रतिभूति के लिए आपने पंजाब नेशनल बैंक, **शाखा: तंजावुर मेन** के पक्ष में साम्यिक बंधक के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिभूतियां सृजित की हैं:

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण

प्रतिभूति का विवरण:-1. श्री आर. चिन्नादुरई के नाम पर अचल संपत्ति व्यावसायिक भूमि जिसका माप 6160 वर्ग फुट (14 सेंट) है, साथ में कार्यशाला, T.S. नं. 522/1, नया सर्वे नं. 522/4, करंबाकुडी गांव (सेट्टी स्ट्रीट), करंबाकुडी उप-पंजीकरण जिला, पुदुकोट्टई पंजीकरण जिला में स्थित है। यह संपत्ति श्री चिन्नादुरई के स्वामित्व में है। **सीमाएं: उत्तर** - वेंकिडाचल देवर भवन **दक्षिण** - प्लॉट नं. 201, 202, 203 एवं 205 **पूर्व** - एम. कादर मैदीन और 6 अन्य की संयुक्त भूमि **पश्चिम** - कुलदैवेल चेट्टियार, चेल्लादुरई चेट्टियार भवन **2. श्री आर. चिन्नादुरई के नाम पर अचल संपत्ति** पुदुकोट्टई जिला, पुदुकोट्टई पंजीकरण जिला, करंबाकुडी उप-पंजीकरण जिला, करंबाकुडी टाउन पंचायत बोर्ड सीमा के अंतर्गत, आलंगुडी तालुक, करंबाकुडी गांव, वनिया स्ट्रीट, T.S. नं. 522/1 में स्थित है। क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट = 125.41 वर्ग मीटर, साथ में 5 RCC दुकानें। **माप: पूर्व-पश्चिम** 47 फुट और उत्तर-दक्षिण 27 फुट, कुल क्षेत्रफल 1269 वर्ग फुट = 117.90 वर्ग मीटर। दरवाजा नं. 54A, 54B, 54C, 54D, 54E E.B.Sc. नं. 876, 904, 905, 907 एवं 908 **सीमाएं: दक्षिण एवं पूर्व** - सुबुरम्मल वगैयारा का खाली प्लॉट **पश्चिम** - कुलदैवेल चेट्टियार का मकान **उत्तर** - मुख्य सड़क **पूर्व-पश्चिम माप:** दोनों ओर 50 फुट **उत्तर-दक्षिण माप:** दोनों ओर 27 फुट कुल क्षेत्रफल: 1350 वर्ग फुट = 125.41 वर्ग मीटर वर्तमान में उपरोक्त संपत्ति करंबाकुडी टाउन में स्थित है।

दिनांक 30.06.2026 तक बैंक को देय राशि रू. 48,19,442.01/- (रुपये अड़तालीस लाख उन्नीस हजार चार सौ बयालीस रुपये एक पैसा मात्र) है, जिसमें 30.06.2026 तक का ब्याज शामिल है। इसके साथ 01.07.2026 से आगे की तिथि से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज + DI भी लगेगा, और पूर्ण भुगतान होने तक यदि कोई वसूली हुई है तो उसे घटाकर देय होगी। इसे आगे 'प्रतिभूत ऋण' कहा जाएगा।

अतः उपरोक्त मांग सूचना के अनुसार आप ऋणी के रूप में उपरोक्त राशि का भुगतान, उस पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित तथा इस सूचना की लागत सहित, बैंक को मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर, मैं अधिकृत अधिकारी प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी या कोई भी अधिकार प्रयोग करूंगा। कृपया ध्यान दें कि मांग सूचना का अनुपालन न करने पर हम उपरोक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने का इरादा रखते हैं। यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इस सूचना की तिथि से प्रतिभूत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से रोका जाता है।

स्थान: मदुरई
दिनांक: 28.07.2026

अधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

विवाद | जाखड़ ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल, हाईकोर्ट ने बनाई जांच समिति

पंजाब में भर्ती विवाद पर भाजपा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) में हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने पारदर्शिता और ईमानदारी के बड़े-बड़े दावे किए थे, उसी के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया कि 28 जनवरी 2026 को जारी विज्ञापन संख्या-126 के तहत की

गई भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला तब सामने आया, जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल एक अभ्यर्थी ने न्याय के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

भाजपा नेता के अनुसार, हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि अदालत की निगरानी में होने वाली जांच से भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है और इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर अनियमितताएं हुई हैं या नहीं।

जाखड़ ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछते हुए कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सब किसी अधिकारी, नेता या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण अथवा सिफारिश से हुआ। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर भी सरकार को घेरा। जाखड़ ने सवाल उठाया कि यदि जांच में अनियमितताएं साबित होती हैं तो क्या सरकार संबंधित मंत्री या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोजगार और भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा नेता ने कहा कि सरकार को इस मामले में जनता के सामने स्पष्ट जवाब रखना चाहिए। उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों और तथ्यों को पारदर्शी तरीके से सामने लाया जाए ताकि अभ्यर्थियों और आम लोगों के बीच पैदा हुए संदेह दूर हो सकें।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों और योजनाओं से जुड़ी भर्तियों में निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होती है।

अमृतसर से 27 देशों तक आसान होगी हवाई यात्रा

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। एयर इंडिया ने अमृतसर से 'ईजी कनेक्ट' सेवा की शुरुआत की है। इस नई सुविधा के तहत पंजाब के यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बेहतर और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सेवा भारत सरकार के हब-एंड-स्पोक मॉडल का विस्तार है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। 'ईजी कनेक्ट' के तहत अमृतसर से विदेश जाने वाले यात्री अपने अंतिम गंतव्य तक का चेक-इन अमृतसर एयरपोर्ट से ही कर सकेंगे। साथ ही इमीग्रेशन प्रक्रिया भी वहीं पूरी हो जाएगी। यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर दोबारा बैगेज चेक-इन करने या टर्मिनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर इंडिया अमृतसर से दिल्ली के लिए रोजाना दो उड़ानों का संचालन करेगी। पहली उड़ान सुबह अमृतसर से रवाना होकर दिल्ली पहुंचेगी, जिससे यात्री यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के कई शहरों से जुड़ सकेंगे।

गुरु पूर्णिमा का संदेश: सूचना से आगे बढ़कर जीवन जीने की कला सिखाता है गुरु

आज हर जेब में ज्ञान का भंडार है। एक समय वह था जब ज्ञान तक पहुँचने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता था। अब समय ऐसा आ गया है कि मोबाइल के जरिए ज्ञान हर जेब तक पहुंच गया है। एक क्लिक पर लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं, हजारों व्याख्यान हैं, अनगिनत वीडियो हैं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ङ्क) तो हर सवाल का उत्तर चुटकियों में देने को तैयार है। कुल मिलाकर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक विशाल डिजिटल पुस्तकालय में बदल दिया है। ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि क्या अब गुरु की आवश्यकता समाप्त हो रही है?

गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें इसी प्रश्न का सबसे सार्थक उत्तर देता है। दरअसल, ज्ञान और गुरु कभी एक-दूसरे के विकल्प नहीं रहे। ज्ञान सूचना दे सकता है, लेकिन गुरु दृष्टि देता है। इंटरनेट तथ्यों का महासागर है, लेकिन उस महासागर में कौन-सा मोती चुनना है, यह विवेक गुरु ही सिखाता है।

आज की जेन जी दुनिया की सबसे अधिक डिजिटल पीढ़ी है। उसके लिए मोबाइल सिर्फ़ फोन नहीं, बल्कि स्कूल, लाइब्रेरी, सिनेमा, बैंक, बाज़ार और मित्र सब कुछ है। वह किसी भी विषय पर कुछ ही सेकंड में जानकारी जुटा सकती है। लेकिन इस पीढ़ी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि जानकारी की अधिकता या सूचनाओं का विस्फोट है।

हजारों उत्तरों के बीच सही उत्तर चुनना, सच और झूठ में अंतर करना, एल्गोरिद्म द्वारा परोसे जा रहे विचारों से स्वतंत्र सोच विकसित करना आज की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह काम कोई सर्च इंजन नहीं बल्कि अच्छा एवं योग्य गुरु ही कर सकता। वरना अब तो गुरु भी नकल और फर्जीवाड़े वाले हो गये हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्व विद्यालय के कुलगुरू रहे श्री टके जी सुरक्षा सर ने तो कहा है कि अब गुरु जी ए आई से किताबें लिख रहे हैं और उसमें ऐसे तथ्य इस्तेमाल कर रहे हैं जो हैं ही नहीं। इसतरह का एक मामला कोर्ट में भी आ चुका है जब फर्जी नतीजों के सहारे जज को गुमराह करने के प्रयास हुए हैं।

मौजूदा दौर में एआई कविता लिख सकता है, शोधपत्र तैयार कर सकता है, चित्र बना सकता है और जटिल समस्याओं का समाधान भी सुझा सकता है लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि किसी निर्णय में संवेदना कहाँ आवश्यक है, नैतिकता किस पक्ष में खड़ी है और मनुष्य होने का असल अर्थ क्या है। यहीं से गुरु की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतीय संस्कृति में गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं रहा। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वह केवल सूचना नहीं देता, बल्कि व्यक्तित्व गढ़ता है। वह केवल करियर नहीं बनाता, बल्कि चरित्र भी बनाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है कि तकनीक उत्तर देती है, लेकिन गुरु प्रश्न पूछना सिखाता है।

सजीव शर्मा
सहायक उप-निदेशक
पीआईबी,शिमला

आज शिक्षा का अर्थ भी बदल रहा है और गुरु का भी। पहले शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत था। अब वह ज्ञान का संरक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। उसका कार्य तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच, नैतिक विवेक, संवाद क्षमता और मानवीय संवेदनाएँ विकसित करना है। नई पीढ़ी को ऐसे गुरु चाहिए जो एआई को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी मानें; जो विद्यार्थियों को उत्तर रटाने के बजाय सही प्रश्न पूछना सिखाएँ।

यह भी सच है कि आज के विद्यार्थी केवल शिक्षक से नहीं सीखते। वे यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स, सोशल मीडिया, ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म और एआई से भी सीख रहे हैं। इसलिए आज गुरु का अधिकार आदेश देने में नहीं, बल्कि अपने आचरण, अनुभव और विश्वसनीयता से अर्जित सम्मान में है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सावन में शिवभक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनता है बैजनाथ मंदिर, देशभर से उमड़ते हैं लाखों श्रद्धालु

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चप्पे-चप्पे पर अनेकों पुरातन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं,जो किसी न किसी किंवदंतियों अथवा जनश्रुतियों से जुड़े हुए हैं। यहां के नित नए मेले-उत्सव व त्योहार यहां की पुरातन सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वैसे भी इस देवभूमि में अनेको देवी-देवताओं व ऋषि-मुनियों का वास रहा है। इसी कड़ी में पठानकोट से 132 किलोमीटर, धर्मशाला-मंडी राज मार्ग पर धर्मशाला से लगभग 56 किलोमीटर, पालमपुर से 16 किलोमीटर तथा समुद्र-तल से ऊंचाई 1250 पर अवस्थित बैजनाथ मंदिर देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था, श्रद्धा व विश्वास का केंद्र है।

वर्षभर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहां विशाल मेला लगता है, जिसे 'तारा रात्रि' के नाम से जाना जाता है और इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु यानी श्रवण मास में बैजनाथ मंदिर में शिवभक्तों का उमड़ता महासैलाब तो देखते ही बनता है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह मंदिर देश के कोने-कोने से शिवभक्तों को आकर्षित करता है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ धाम भी है। 9वीं शताब्दी में निर्मित शिखराकार शैली के इस मंदिर में पुरातन शिवलिंग का पूजन होता है। बैजनाथ का प्राचीन नाम कीरग्राम था। मंदिर से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार, मयुक और आहुक नाम के दो व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जनश्रुति अनुसार, 1776-1824 में राजा संसार चंद कटोच ने अपने शासनकाल में इस मंदिर की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई थी। बैजनाथ मंदिर की पौराणिक कथा अनुसार, त्रेतायुग में चार वेदों के ज्ञाता रावण ने हिमालय के कैलाश पर्वत पर शिवजी के निमित्त तपस्या की। कोई फल न मिलने पर रावण ने पुन: घोर तपस्या प्रारंभ की। अंत में उसने अपना एक-एक सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू किया।

दसवां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने उसके सभी सिरों को पुनर्स्थापित कर जाने से पूर्व शिवजी ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने कहा 'मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूं। आप दो भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें।' शिवजी ने तथास्तु कहा और लुप्त हो गए। लुप्त होने से पूर्व शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप दो चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला और रास्ते में गौकर्ण क्षेत्र यानी बैजनाथ में पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी।

किंवदंतियों अनुसार, उसने बैजु नाम के ग्वाले को सब बात समझा कर शिवलिंग पकड़ा दिए और लघुशंका निवारण के लिए चला गया, शिवजी की माया के कारण बैजु उन शिवलिंगों के वजन को अधिक देर न सह सका और उसने उन्हें धरती पर रख दिया और अपने पशु चराने चला गया। इस प्रकार दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया।

डॉ. अंकिता चौधरी
(सह-प्राध्यापक) अभिलाषी
विश्वविद्यालय, मंडी (हि .प्र.)

सावन माह में बैजनाथ का समस्त क्षेत्र आस्था और देवतुल्य शिवमय से सराबोर हो जाता है। सावन माह के बाहर प्रांगण व अंदर विराजमान शंकर भगवान का शिवलिंग,नंदी व अन्य कलात्मक और भव्य मूर्तियां एक अलग ही श्रद्धा की अनुभूति कराती हैं, जिनके आगे भक्तजन नतमस्तक हुये बगैर नहीं रह सकते। इस बार बैजनाथ शिव मंदिर में सावन के चार सोमवार होंगे जोकि 20 जुलाई से दस अगस्त के मध्य तक चलेंगे। किंवदंतियों के अनुसार, भगवान शिव को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है। वैसे भी शिव भगवान सर्वव्यापी हैं। सावन माह में बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस अवसर पर 10 दिनों तक भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

> **अंधेरा** कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है
> -हरिवंश राय बच्चन

संपादकीय

एथेनॉल: सभी शंकाओं का समाधान करे सरकार

भारत तेजी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की नीति को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी ई-20 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यह केवल ईंधन में बदलाव नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण में कमी लाना, किसानों की आय बढ़ाना और जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। हालांकि सरकार इस नीति को भविष्य के भारत के लिए महत्वपूर्ण मान रही है, लेकिन आम लोगों, वाहन मालिकों और विशेषज्ञों के मन में इससे जुड़े कई सवाल अब भी मौजूद हैं। किसी भी बड़ी नीति की सफलता तभी संभव है, जब उसके प्रति जनता का विश्वास मजबूत हो और सभी आशंकाओं का पारदर्शी समाधान किया जाए।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में तेल आयात पर खर्च होते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ता है। ऐसे में सरकार लंबे समय से ऐसे विकल्पों की तलाश कर रही थी, जिनसे पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम की जा सके। एथेनॉल इसी दिशा में एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है। यह गन्ने के शीरे, मक्का, टूटे हुए चावल तथा अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाने वाला जैव ईंधन है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और किसानों को अपनी उपज का अतिरिक्त बाजार मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत लगातार बढ़ाया गया है। पहले जहां यह केवल कुछ प्रतिशत तक सीमित था, वहीं अब ई-20 के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है। संसद में भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नीति को लागू करने से पहले विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, जिनसे यह साबित हो कि ई-20 से वाहनों के इंजनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है।

इसके बावजूद वाहन मालिकों की चिंताएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे दोपहिया और चारपहिया वाहन चल रहे हैं, जिनका निर्माण उस समय हुआ था, जब ई-20 ईंधन का उपयोग सामान्य नहीं था। ऐसे वाहन मालिक यह जानना चाहते हैं कि क्या उनका इंजन लंबे समय तक इस ईंधन के उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। क्या इससे इंजन के पुर्जों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, माइलेज में कमी आएगी या रखरखाव का खर्च बढ़ेगा? सरकार ने संसद में यह स्वीकार किया कि ई-20 समर्थित वाहनों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। हालांकि परीक्षणों के आधार पर इंजन को किसी बड़े नुकसान से इनकार किया गया है, लेकिन यदि कुछ परिस्थितियों में माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है या पुराने वाहनों के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, तो यह जानकारी भी पूरी स्पष्टता के साथ सार्वजनिक की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम और अफवाहों को जन्म देती है।

एथेनॉल नीति का सबसे सकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर दिखाई देता है। भारत में लंबे समय से गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान में देरी और चीनी उद्योग की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से चीनी मिलों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है, जिससे किसानों के बकाया भुगतान में सुधार की संभावना बढ़ी है। इसी प्रकार मक्का उत्पादक किसानों के लिए भी यह एक नया बाजार लेकर आया है। यदि कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है तो किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बल मिल रहा है।

हालांकि इस नीति के साथ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा प्रश्न खाद्य सुरक्षा का है। यदि बड़ी मात्रा में गन्ना, मक्का और अन्य खाद्यान्न फसलें ईंधन उत्पादन के लिए उपयोग होने लगें, तो भविष्य में खाद्य उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से गन्ना ऐसी फसल है, जिसकी सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। भारत के कई हिस्से पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यदि एथेनॉल उत्पादन का विस्तार केवल गन्ने पर आधारित रहेगा, तो भूजल स्तर और जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि नीति निर्माण के दौरान जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को समान महत्व दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में दूसरी पीढ़ी यानी टू-जी एथेनॉल पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

-शिवांश धाकड़

कविता

मैं एक वर्षा की बूंद

अतुल कुमार, गांव गड़खल, तहसील कसौली
जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) 173201

सूरज और सागर के मिलन से जन्म ले खड़ी हूं
बादलों रूपी रथ चढ़कर मैं चल पड़ी हूं।।
धरती से मिलने, फूलों में खिलने
नदियों से खेलने, पत्थरों को झेलने।।
फसलों में घुलने, फल फूल में झूलने।।
हरियाली बिखेरने, जीवनचक्र फेरने।।
मेरा होगा बलिदान, खुश होगा किसान
खुश होगा बागवान, बनेगा कोई मकान।।
सेहत का रखने ध्यान, पवित्र करने स्नान
जीव को देने जान, घर आए को सम्मान।।
बनने को पानी, नदियों की कहानी
झीलों की जवानी, जग को दिखानी।।
रसोई है बनानी, दवा है खिलानी
पूजा है करानी, जान है बचानी
सागर से आना, फिर सागर से मिल जाना

भ्रष्टाचार की जड़ विचारों में छिपी है, केवल व्यवस्था बदलने से नहीं बदलेगा समाज

हम अक्सर भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। समाचारों में घोटालों की सुर्खियां पढ़ते हैं, रिश्वतखोरी पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, नेताओं और अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं और यह मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार केवल धन के लेन-देन तक सीमित है, परंतु क्या कभी हमने स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि रिश्वत लेने वाला हाथ पहले भ्रष्ट हुआ था या उससे पहले उसका मन? क्या किसी घोटाले की शुरुआत तिजोरी से होती है, या उससे बहुत पहले विचारों में जन्म लेती है?

सच तो यह है कि हर आर्थिक भ्रष्टाचार की पहली ईंट विचारों के भ्रष्टाचार से रखी जाती है। जब मनुष्य का विवेक स्वार्थ के सामने झुक जाता है, जब सत्य सुविधा के सामने हार जाता है, जब चरित्र लाभ के सामने बिक जाता है, तभी भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इसलिए यदि हमें भ्रष्टाचार का वास्तविक उपचार खोजना है, तो उसकी जड़ तक पहुंचना होगा और वह जड़ है विचारों की भ्रष्टता। उपनिषदों में कहा गया है-'यद्भावं तद्भवति' अर्थात जैसे विचार होंगे, वैसा ही जीवन बनेगा। मनुष्य पहले विचारों में निर्माण करता है, फिर वही विचार उसके कर्मों में उतरते हैं और अंतत: समाज तथा राष्ट्र का चरित्र बन जाते हैं।

यदि विचारों में लोभ, छल, घृणा और अहंकार होगा तो व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अंतत: खोखली हो जाएगी। आज भारत केवल आर्थिक या तकनीकी परिवर्तन के दौर से नहीं गुजर रहा, बल्कि वैचारिक संक्रमण के दौर से भी गुजर रहा है। सूचना का विस्फोट हुआ है, लेकिन विवेक का विस्तार उतनी गति से नहीं हुआ। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, परंतु उसी मंच पर असत्य, कटुता, अफवाह, चरित्र-हनन और नफरत भी अभूतपूर्व गति से फैल रही है। दुखद यह है कि झूठ अब केवल बोला नहीं जाता, उसे योजनाबद्ध ढंग से फैलाया भी जाता है। जब असत्य को बार-बार दोहराया जाता है, तब वह अनेक लोगों के लिए सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। यही वैचारिक भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप है। आज समाज में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग गलतियां करते हैं; सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग अपनी गलतियों को सही सिद्ध करने लगे हैं। ईमानदारी को मूर्खता और छल को चतुराई समझा जाने लगा है।

सुभाष चंद काशव
जौवा, गैहरा, जिला चंबा

सफलता का मापदंड चरित्र नहीं, केवल परिणाम बनता जा रहा है। ऐसी मानसिकता में भ्रष्टाचार अपवाद नहीं रहता, बल्कि सामान्य व्यवहार बन जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल कानूनी शब्द नहीं हैं; वे शुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति हैं। जब हम जाति, धर्म, भाषा या राजनीतिक मतभेद के आधार पर एक-दूसरे के प्रति घृणा पालते हैं, तब हम केवल सामाजिक सौहार्द नहीं तोड़ते, बल्कि संविधान की आत्मा को भी कमजोर करते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वास्तविक संघर्ष व्यक्ति के अंत:करण से शुरू होता है। लोकतंत्र नागरिकों की नैतिक चेतना, जिम्मेदारी और ईमानदार व्यवहार से जीवित रहता है।

राजनीति का मूल उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए, न कि केवल सत्ता प्राप्त करना। भ्रष्टाचार केवल सरकारी तंत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार से भी जुड़ा है। जब हम नियमों को अपने लिए कमजोर समझते हैं, बिना जांचे सूचनाएं फैलाते हैं या सफलता को केवल धन और पद से आंकते हैं, तब हम भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नागालैंड शांति प्रक्रिया का ऐतिहासिक मोड़: 30 जुलाई 2015 को अंतिम दौर की वार्ता हुई सफल

30 जुलाई 2015 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन भारत सरकार और (एनएससीएन-आईएम) के बीच लंबे समय से चल रही शांति वार्ताओं का अंतिम चरण पूरा हुआ, जिसके बाद 3 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक **फ्रेमवर्क एग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर नागालैंड में दशकों से चले आ रहे उग्रवाद और हिंसा को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना गया।

नागा आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता से भी पहले का है। नागा समुदाय की कुछ संस्थाओं ने अलग पहचान और स्वायत्तता की मांग उठाई थी। आजादी के बाद यह मांग धीरे-धीरे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गई। समय के साथ कुछ संगठनों ने हथियार उठा लिए और अलग नागा राष्ट्र की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष के कारण नागालैंड और आसपास के राज्यों में कई दशकों तक हिंसा, अस्थिरता और विकास में बाधा बनी रही। हजारों लोगों की जान गई और सामान्य नागरिकों का जीवन भी प्रभावित हुआ।

वर्ष 1980 में एनएससीएन संगठन का गठन हुआ, जो बाद में दो प्रमुख गुटों में बंट गया। इनमें से एक था **एनएससीएन-आईएम**, जिसका नेतृत्व इसाक चिशी स्वू और थुइंगलेंग मुइवा कर रहे थे। यह संगठन लंबे समय तक भारत सरकार के साथ संघर्ष करता रहा। हालांकि वर्ष 1997 में भारत सरकार और एनएससीएन-आईएम के बीच युद्धविराम लागू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अगले लगभग 18 वर्षों तक विभिन्न दौर की वार्ताएं चलती रहीं। इन बैठकों में राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक विकास और शांति बहाली जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।

साल 2015 तक दोनों पक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति के करीब पहुंच चुके थे। जुलाई 2015 में वार्ताओं का अंतिम चरण पूरा हुआ, जिसने समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। इसके कुछ ही दिनों बाद 3 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार और एनएससीएन-आईएम के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता विश्वास, सम्मान और साझा भविष्य की भावना पर आधारित है।

फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का उद्देश्य नागा समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का सम्मान करते हुए भारत की संप्रभुता और संवैधानिक व्यवस्था के भीतर स्थायी समाधान खोजना था। समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे शांति, विकास और सहयोग की दिशा में एक नई शुरुआत बताया।

डॉ. दमन आहूजा
जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक
विकास विशेषज्ञ

इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि वर्षों से हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति का वातावरण मजबूत होने लगा। सुरक्षा संबंधी घटनाओं में कमी आई और विकास परियोजनाओं को गति देने की संभावना बढ़ी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों को नई ऊर्जा मिली।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मित्रता की शक्ति से बनेगा शांतिपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस का यही है मूल संदेश

हर वर्ष 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल मित्रों के साथ शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करने का अवसर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, सहयोग और आपसी विश्वास का संदेश देने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में यह निर्णय लिया कि 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों, समाजों, संस्कृतियों और देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देकर विश्व में शांति और आपसी समझ को मजबूत करना है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों, संघर्षों, हिंसा, भेदभाव और सामाजिक विभाजनों का सामना कर रही है तब मित्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

मित्रता एक ऐसा संबंध है जो किसी जाति, धर्म, भाषा, रंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति की सीमाओं में बंधा नहीं होता। यह विश्वास, सम्मान, सहयोग और स्नेह पर आधारित होता है। एक सच्चा मित्र कठिन परिस्थितियों में साथ खड़ा रहता है और जीवन के हर उतार-चढ़ाव में प्रेरणा तथा हौसला देता है। यही कारण है कि मित्रता को मानव जीवन का सबसे मूल्यवान संबंध माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि यदि समाज और देशों के बीच मित्रता और सहयोग की भावना मजबूत होगी तो संघर्षों की संभावना कम होगी और शांति का मार्ग आसान बनेगा। अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस का मूल संदेश यही है कि विभिन्न संस्कृतियों, समुदायों और देशों के लोग एक-दूसरे को समझें, सम्मान दें और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ें। मित्रता केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता नहीं है बल्कि यह समाजों और राष्ट्रों के बीच विश्वास का पुल भी है।

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में मित्रता का विशेष महत्व है। यहां अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद लोग मिल-जुलकर रहते हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यस्थलों और सामाजिक जीवन में बनने वाली मित्रताएं लोगों को एक-दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने का अवसर देती हैं। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती है और भाईचारे की भावना विकसित होती है।

भारतीय संस्कृति में भी मित्रता को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण मानी जाती है। दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग होने के बावजूद उनका स्नेह और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान श्रीराम और निषादराज गुह की मित्रता समानता, सम्मान और समर्पण का संदेश देती है। महाभारत में श्रीकृष्ण और अर्जुन की मित्रता केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि मार्गदर्शन, विश्वास और कर्तव्य की प्रेरणा का प्रतीक है। ये उदाहरण बताते हैं कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं बल्कि निष्ठा और विश्वास से बनती है।

हरिराम धीमान
स्वतंत्र लेखक, नालागढ़

आज का समय डिजिटल युग का है। सोशल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यमों ने लोगों को जोड़ना आसान बना दिया है। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग कुछ ही क्षणों में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह तकनीक नई मित्रताओं के अवसर प्रदान करती है लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। आभासी दुनिया में बनने वाले सभी संबंध वास्तविक नहीं होते। इसलिए डिजिटल मित्रता में भी सावधानी, विश्वास और जिम्मेदारी आवश्यक है। सच्ची मित्रता केवल संदेशों और लाइक तक सीमित नहीं होती बल्कि कठिन समय में साथ निभाने और एक-दूसरे का सम्मान करने से मजबूत होती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

सुरों के सरताज सोनू निगम

सोनू निगम का जन्म **30 जुलाई** 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। वे भारतीय संगीत जगत के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी पार्श्व गायकों में गिने जाते हैं। बचपन से ही उन्हें संगीत का वातावरण मिला। उनके पिता अगम कुमार निगम स्वयं एक गायक थे और सोनू ने बहुत छोटी उम्र में ही मंच पर गाना शुरू कर दिया था। महज चार वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति दी, जिसके बाद संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया।

सोनू निगम
जन्म : 30 जुलाई 1973

अपने सपनों को साकार करने के लिए सोनू निगम मुंबई आए और लंबे समय तक संघर्ष किया। शुरुआती दौर में उन्होंने कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया और विभिन्न मंचों पर अपनी गायकी का प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें हिंदी फिल्मों में गाने का अवसर मिला। फिल्म बेवफा सनम का गीत अच्छा सिला दिया उनकी शुरुआती बड़ी सफलताओं में से एक रहा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक अनेक सुपरहिट गीत गाए।

सोनू निगम की आवाज़ की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मधुरता, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और हर तरह के गीत को सहजता से गाने की क्षमता है। उन्होंने रोमांटिक, सूफी, भक्ति, देशभक्ति और भावनात्मक गीतों को अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत किया। हिंदी के अलावा उन्होंने कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, नेपाली और कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उनकी बहुभाषी गायकी ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बनाया।

गायन के साथ-साथ सोनू निगम ने कई संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी भी की और विभिन्न रियलिटी शो में निर्णायक की भूमिका निभाई। वे नए गायकों को प्रोत्साहित करने और संगीत की नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भी जाने जाते हैं। उनका विनम्र स्वभाव और संगीत के प्रति समर्पण उन्हें प्रशंसकों के बीच विशेष स्थान दिलाता है। अपने शानदार करियर में सोनू निगम को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और कई अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

फतेहगढ़ के ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में दौड़ लगा रहे युवक की मौत, अग्निवीर की कर रहा था तैयारी

एजेंसी, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में बुधवार सुबह दौड़ लगाते समय एक युवक की मौत हो गई। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम शेरा खार निवासी शिवनारायण (18) पुत्र मुनेश्वर सिंह अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था। वह रोज की तरह सुबह स्टेडियम में दौड़ लगाने पहुंचा था। इसी दौरान अचानक उसे चक्कर आया और सीने में दर्द होने लगा। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिवार में मातम छा गया। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। सीएमओ आनंद उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

अमेठी में 12वीं की नाबालिग छात्रा लापता, मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

एजेंसी, अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी कोतवाली क्षेत्र में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार छात्रा 24 जुलाई को मामा के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। छात्रा के पास मोबाइल फोन नहीं होने से संपर्क भी नहीं हो पाया। 28 जुलाई को छात्रा की मां ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी है।

बेकाबू स्कूल वैन खाई में पलटी, शिक्षिका समेत 12 से अधिक बच्चे घायल

एजेंसी, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एस.एस. पब्लिक स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में शिक्षिका समेत 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार वैन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। बेलवार के पास मोड़ पर चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिससे दुर्घटना हुई। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकालकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन के फिटनेस व सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगाई हाजिरी

एजेंसी, वाराणसी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में बाबा के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उपमुख्यमंत्री ने बाबा से देश और प्रदेश में शांति, सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि सावन माह के शुभारंभ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं।

एडमिशन नहीं मिला तो छात्र ने हैक की आईआईटी कानपुर वेबसाइट

एजेंसी, कानपुर। आईआईटी कानपुर में प्रवेश नहीं मिलने पर एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट हैक करने का दावा किया है। छात्र ने बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन किया था। उसने वेबसाइट पर संदेश लिखा- 'मुझे बस एक मौका चाहिए।' इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर हैकिंग के स्क्रीनशॉट साझा किए। मामला सामने आने पर आईआईटी प्रबंधन ने पहले कानूनी कार्रवाई पर विचार किया, लेकिन छात्र के भविष्य को देखते हुए निर्णय बदला। निदेशक मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि छात्र की साइबर क्षमता जांचने के लिए उसे दोबारा टेस्ट का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने अवैध तरीके से सिस्टम में प्रवेश को गलत बताया।

यूपी में बंद नहीं होंगे प्राथमिक विद्यालय कम नामांकन वाले स्कूलों का होगा विलय

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लिया जा रहा है निर्णय

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी प्राथमिक विद्यालय को बंद नहीं किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या काफी कम है, उन्हें आसपास के अन्य विद्यालयों में विलय किया जाएगा, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

लोकसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना पक्ष रखा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य विद्यालयों को बंद करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।

उन्होंने बताया कि कम नामांकन वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, पर्याप्त शिक्षक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार का मानना है कि कम छात्र संख्या वाले कई विद्यालयों में संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विद्यालयों के विलय से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। संदीप सिंह ने यह भी जानकारी दी कि जिन विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होंगी, वहां पहली बार प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक नई पहल होगी। प्री-प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से छोटे बच्चों को विद्यालयी सीखने से जोड़ने और उनकी सीखने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग का कहना है कि विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होगी और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विद्यालयों के पुनर्गठन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों, बच्चों की संख्या और दूरी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्णय में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के बजाय उसे अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है।

प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध : सूर्यप्रताप शाही

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें। लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 28.82 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है।

उर्वरक उपलब्धता को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क

इसमें यूरिया 14.52 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 4.81 लाख मीट्रिक टन और एनपीके 4.91 लाख मीट्रिक टन शामिल है। इसके अलावा एसएसपी 3.47 लाख मीट्रिक टन और एमओपी 1.11 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से 27 जुलाई तक प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सहकारिता क्षेत्र में यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, जबकि निजी बिक्री केंद्रों पर भी किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन हजारों मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी और एनपीके की खरीद एवं खपत किसानों द्वारा की जा रही है।

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें। कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, डॉ. भूपेश गोयल संभालेंगे कमान

एजेंसी, नोएडा

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. भूपेश कुमार गोयल की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम–2019 के तहत कुलाधिपति की स्वीकृति के बाद हुई है। उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या अगले आदेश तक रहेगा।

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति, कार्यकाल पांच वर्ष

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव ने बताया कि डॉ. गोयल भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने महानिदेशक (ऑर्गनाइजेशन एंड पर्सनेल) के रूप में 14 हजार से अधिक अधिकारियों के मानव संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक पुनर्गठन की जिम्मेदारी संभाली। डॉ. गोयल पुणे के कमांड हॉस्पिटल सहित कई प्रमुख सैन्य अस्पतालों का नेतृत्व कर चुके हैं।

झांसी में खड़े ट्रक से स्लीपर बस टकराई, चालक समेत दो की मौत

एजेंसी, झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में बस चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 20 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार प्रयागराज से मध्य प्रदेश के विदिशा जा रही एक स्लीपर बस देर रात करीब एक बजे बड़गांव क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मध्य प्रदेश निवासी बस चालक इस्लाम बेग और यात्री कन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया।

बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन पुरानी पत्रावली व्यवस्था बहाल करने की मांग

एजेंसी, देवरिया

सदर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को तहसील परिसर में न्यायिक कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष किशोर तिवारी एडवोकेट के नेतृत्व में और मंत्री विजयसेन यादव एडवोकेट के संचालन में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वर्षों पुरानी पत्रावली (अभिलेख) व्यवस्था को दोबारा लागू करने की मांग की।

प्रदर्शन के बाद आयोजित आमसभा में अधिवक्ताओं ने कहा कि पत्रावली व्यवस्था में बदलाव के बाद न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समय पर अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पुरानी व्यवस्था को तत्काल बहाल किया जाए, जिससे न्यायिक कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

आमसभा में तहसील कार्यालय में कुशल कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण राजस्व और न्यायिक मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है। बैठक के दौरान संगठन के विभिन्न पदों पर मनोनयन भी किया गया।

ट्रक ने साइकिल से घर लौट रहे हाई स्कूल के छात्र को रौंदा, मौत के बाद चालक फरार

एजेंसी, बलरामपुर

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर में बुधवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हाईस्कूल के एक छात्र की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल से घर लौट रहे छात्र को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

मृतक की पहचान तुलसीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर निवासी बजरंगी के 13 वर्षीय पुत्र अरुण के रूप में हुई है। अरुण बसंत लाल इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। बताया गया कि बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वह अपनी चचेरी बहन के साथ साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान तुलसीपुर रेलवे स्टेशन रोड पर मवाशी लाल शर्मा ट्रक बॉडी की दुकान के सामने पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

सूचना पर पहुंची तुलसीपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने विभिन्न जगहों पर छह लोगों से की लूटपाट

एजेंसी, फर्रुखाबाद

नोएडा के अलग–अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने आधा दर्जन लोगों को निशाना बनाते हुए मोबाइल फोन और सोने की चेन लूट ली। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सेक्टर–63 क्षेत्र में एक कंपनी कर्मचारी सात्विक का मोबाइल फोन बदमाश ने लूट लिया। वहीं सेक्टर–20 क्षेत्र में आलोक कुमार से फोन छीनकर बदमाश फरार हो गया। सेक्टर–19 निवासी टीया का आईफोन बाइक सवार दो बदमाशों ने सेक्टर–27 मार्केट के पास छीन लिया।

नोएडा में लगातार लूट की घटनाएं, बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक

इसके अलावा सेक्टर–24 क्षेत्र में प्रियांशी बरयानी से यू–टर्न के पास दो बदमाशों ने आईफोन लूट लिया। फेस–1 थाना क्षेत्र में अमन पांडे का मोबाइल फोन बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया। बिसरख थाना क्षेत्र में गौर सिटी–7 एवेन्यू निवासी आकाश राय से बाइक सवार बदमाशों ने करीब दो तोले वजन की सोने की चेन लूट ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

मीरजापुर में फांसी लगा कर युवक व विवाहिता ने दी जान

एजेंसी, मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की दो अलग–अलग घटनाओं में एक युवक और एक विवाहिता की मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पहली घटना अहरौरा थाना क्षेत्र के बूढ़ादेई मोहल्ले की है। यहां 25 वर्षीय अब्दुल कयूम उर्फ रहीम ने मंगलवार देर रात अपने ससुराल की छत पर बने पिलर में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक के पिता अब्दुल करीम की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। अब्दुल कयूम ने चार साल पहले प्रेम विवाह किया था और वह पत्नी व तीन वर्षीय बेटी के साथ रहकर ड्राइविंग का काम करता था।

दूसरी घटना लालगंज थाना क्षेत्र के गंगहरा कला गांव की है। यहां 23 वर्षीय गंगोत्री देवी का शव बुधवार सुबह घर में फंदे से लटका मिला। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी के चार साल बाद भी संतान नहीं होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं और उनका इलाज चल रहा था। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

गुरु के बिना ज्ञान अधूरा, जीवन में नहीं मिलता सही मार्ग : महंत आनंद शेखर

एजेंसी, मीरजापुर

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्री महंत आनंद शेखर गिरी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। गुरु की कृपा के बिना मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता और न ही जीवन का सही मार्ग प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के निर्माण में गुरु की भूमिका सर्वोपरि होती है।

गुरु व्यक्ति के अंदर छिपी बुराइयों, अज्ञानता और भ्रम को दूर कर उसे सत्य, धर्म और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक समाज और राष्ट्र के निर्माण में गुरुओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। महंत आनंद शेखर गिरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। माता–पिता व्यक्ति को जन्म और संस्कार देते हैं, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु–शिष्य परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली परंपराओं में शामिल है। इतिहास में गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं।

उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे गुरु का सम्मान करें और उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति सम्मान और आस्था रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। गुरु का मार्गदर्शन कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को बेहतर बनाने का आह्वान किया।

बुद्धवाणी

धम्मचक्क पवत्तन दिवस पर सारनाथ से दिया गया विश्व शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का संदेश

भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को दुनिया कर रही स्वीकार : केशव प्रसाद मौर्य

एजेंसी, वाराणसी

आषाढ़ पूर्णिमा एवं धम्मचक्क पवत्तन दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को ऐतिहासिक सारनाथ भगवान बुद्ध के उपदेशों, शांति और मानव कल्याण के संदेशों से गूंज उठा। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी), नई दिल्ली और केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशेष समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी, विद्यार्थी, भिक्षु और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग पूरी दुनिया के लिए शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का मार्ग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। पूरी दुनिया आज बुद्ध के संदेशों को स्वीकार कर रही है और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले रही है।

उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने समाज को करुणा, अहिंसा, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उनके विचार केवल किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। बुद्ध के उपदेशों ने विश्व में शांति और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का काम किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों और विरासत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। सरकार का प्रयास है कि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को इन ऐतिहासिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि सारनाथ जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बौद्ध स्थलों के संरक्षण, विकास और धार्मिक–सांस्कृतिक आयोजनों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान बुद्ध के विचारों के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था यह साबित करती है कि उनकी शिक्षाएं आज भी मानव समाज को सही दिशा देने में सक्षम हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव शार्त्से खेंसुर जंगचुप चोएडेन रिनपोछे के स्वागत भाषण से हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गौरतलब है कि बौद्ध परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के सात सप्ताह बाद भगवान बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को बौद्ध परंपरा में धम्मचक्क पवत्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है।

मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

एजेंसी, गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने 200 लोगों की समस्याएं सुनीं

गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के पास पहुंचे और एक–एक कर उनकी शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों को सुना। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।

इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को योगी ने दिया भरोसा

उन्होंने लोगों की समस्याओं से जुड़े प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की जांच कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का समाधान इस तरह किया जाए, जिससे लोगों को वास्तविक राहत मिल सके और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनता दर्शन के दौरान कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे।

मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज से संबंधित अनुमानित खर्च की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजी जाए, ताकि सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ पहुंचे बच्चों से भी मुलाकात की।

गुरुग्राम में 171 करोड़ की 26 विकास परियोजनाओं को मंजूरी, सदर बाजार में लगेंगे 235 सीसीटीवी कैमरे

एफएंडसीसी बैठक में विभिन्न वार्डों के सड़क निर्माण, पाइपलाइन विस्तार और स्ट्रीट लाइट से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

नगर निगम गुरुग्राम की वित्त एवं संविदा समिति (एफएंडसीसी) ने शहर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 171 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सड़क, पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

साथ ही सदर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 235 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी। मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित वित्त एवं संविदा समिति की नौवीं बैठक में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहर के अलग-अलग वार्डों में सड़क निर्माण और पुनर्निर्माण, पेयजल पाइपलाइन विस्तार, नई सीवर लाइन बिछाने, वर्षा जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यों से लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे कई क्षेत्रों को राहत मिलेगी।

सदर बाजार आधुनिक निगरानी प्रणाली और कैमरों से होगा सुरक्षित।

नगर निगम के अनुसार, सदर बाजार में लगाए जाने वाले 235 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाजार में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने, यातायात व्यवस्था सुधारने और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने में यह परियोजना सहायक होगी। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक आधारित सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिससे पानी की आपूर्ति, रिसाव और वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य केवल नई सुविधाएं विकसित करना नहीं, बल्कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाना है। कई क्षेत्रों में पुरानी सड़कों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य कराए जाएंगे। इससे बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

कांवड़ यात्रा के चलते 11 अगस्त तक बंद रहेंगी यमुनानगर की लक्कड़ मंडियां

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

सावन माह और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यमुनानगर की प्रसिद्ध लक्कड़ मंडियां 11 अगस्त तक बंद रहेंगी। मंडियों के बंद रहने से जिले के लकड़ी आधारित उद्योगों, विशेषकर प्लाईवुड सेक्टर पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। उद्योग जगत का कहना है कि कच्चे माल की आपूर्ति रुकने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है और कई इकाइयों को सीमित क्षमता पर काम करना पड़ सकता है।

यमुनानगर देश के प्रमुख प्लाईवुड उद्योग केंद्रों में शामिल है। यहां करीब 350 प्लाईवुड फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया काफी हद तक लक्कड़ मंडियों से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर करती है। मंडियों में लकड़ी की आवक बंद होने से उद्योगों के सामने कच्चे माल का संकट खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। कई उद्योगपतियों का कहना है कि यदि बंदी लंबी चली तो उत्पादन लागत और आपूर्ति श्रृंखला दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

दूसरी ओर, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कई स्थानों पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

रेलवे की ओर से भी कांवड़ यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। व्यापारियों का कहना है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए हर वर्ष इस अवधि में मंडियां बंद रखी जाती हैं। हालांकि इस दौरान उद्योगों को पहले से उपलब्ध स्टॉक के सहारे उत्पादन जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। उद्योग जगत को उम्मीद है कि 11 अगस्त के बाद मंडियां खुलने पर लकड़ी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी और उत्पादन गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ लेंगी। प्रशासन ने उद्योगों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने को कहा।

न्यूज ब्रीफ

प्रेम विवाह के नौ साल बाद पति की प्रताड़ना से परेशान महिला ने तेजाब पीकर दी जान

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले के तहसील कैंप थाना क्षेत्र स्थित वधवाराम कॉलोनी में 29 वर्षीय महिला ने कथित रूप से तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान नेहा के रूप में हुई है। बताया गया कि उसने करीब नौ वर्ष पहले अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद प्रेम विवाह किया था। परिजनों का आरोप है कि उसका पति शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था, जिससे वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। नेहा अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं से घटना की पड़ताल की जा रही है।

ई-20 पेट्रोल से डिफेंडर का फ्यूल पंप खराब गायक रेशम सिंह अनमोल ने उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला। पंजाबी गायक रेशम सिंह अनमोल ने अपनी लैंड रोवर डिफेंडर का फ्यूल पंप खराब होने के मामले में ई-20 (एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने दावा किया कि पहली सर्विस के कुछ समय बाद ही उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। अधिकृत सर्विस सेंटर में जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि खराब पेट्रोल के कारण फ्यूल पंप क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे बदलना पड़ेगा। गायक ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन पर एजेंडा चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय से प्रीमियम गुणवत्ता का पेट्रोल उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंपों की आधिकारिक सूची जारी करने की मांग की है, ताकि वाहन चालकों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

जन्मदिन पार्टी में गया परिवार, पीछे से चोरों ने घर खंगालकर लाखों का उड़ाया, सामान

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेहतपुर स्थित सूर्या कॉलोनी में कच्छा गैंग ने एक सूने मकान में लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से करीब पांच लाख रुपये के सोने के जेवर, लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना के समय परिवार पड़ोस में आयोजित जन्मदिन समारोह में गया हुआ था। पीड़िता शहनाज ने बताया कि उनके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और वह अपनी दो बेटियों के साथ रहती हैं। सुबह घर लौटने पर ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो संदिग्ध युवक केवल कच्छा पहने चोरी का सामान ले जाते दिखाई दिए हैं। पल्ला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

हिसार रेलवे स्टेशन पर एलपीजी लीकेज सतर्कता से टला बड़ा हादसा

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हिसार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के एलपीजी टैंकर से बुधवार सुबह गैस रिसाव होने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने सुबह करीब आठ बजे टैंकर से गैस लीक होती देख तत्काल रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। एहतियात के तौर पर रिसाव वाले टैंकर को मालगाड़ी से अलग कर स्टेशन से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सूचना मिलते ही तकनीकी टीम और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। विशेषज्ञों ने समय रहते लीकेज को नियंत्रित कर स्थिति पर काबू पा लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मालगाड़ी बठिंडा से झज्जर की ओर जा रही थी। समय पर कार्रवाई होने से किसी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर रोज 90 हजार खर्च, कमाई सिर्फ 7 हजार रुपए

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल जींद-सोनीपत रेलखंड पर संचालित हो रही है, लेकिन शुरुआती आंकड़े इसके आर्थिक पक्ष को चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन के संचालन में प्रतिदिन केवल हाइड्रोजन गैस पर लगभग 80 से 90 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि टिकटों से होने वाली आय करीब सात हजार रुपये प्रतिदिन ही है। इस प्रकार संचालन खर्च ट्रेन की आय से लगभग 12 गुना अधिक बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, जींद से सोनीपत के बीच ट्रेन की कुल दूरी करीब 160 किलोमीटर है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन पर प्रति किलोमीटर लगभग 500 रुपये का खर्च आता है। गैस के अतिरिक्त रखरखाव, तकनीकी निगरानी, सुरक्षा प्रबंधन और अन्य परिचालन खर्च भी अलग से वहन करने पड़ रहे हैं।

कम यात्रियों से बढ़ा हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन घाटा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद रेलवे स्टेशन से इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद से ट्रेन नियमित रूप से संचालित की जा रही है। ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7:40 बजे जींद से सोनीपत के लिए रवाना होती है। यात्रियों की संख्या अभी अपेक्षाकृत कम है। जींद से सोनीपत जाने वाले यात्रियों की संख्या 50 के आसपास बनी हुई है, जबकि सोनीपत से जींद आने वाले यात्रियों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है।

मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। लगातार बारिश के बीच डबुआ कॉलोनी में एक मकान का छज्जा गिरने से 28 वर्षीय लाडली खातून की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय वह छज्जे पर खड़ी थीं और छज्जे के साथ नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लाडली मूल रूप से बिहार के सारण जिले की रहने वाली थीं और अपने पति कुसमा मोहम्मद तथा छह महीने की बेटी के साथ दो महीने पहले ही रोजगार की तलाश में फरीदाबाद आई थीं। परिवार डबुआ कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। डबुआ थाना पुलिस के अनुसार फिलहाल मकान मालिक के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

हाई कोर्ट ने एएलएस पीड़ित कर्मचारी को 3.95 लाख रुपए और पूरा वेतन देने का दिया आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एएलएस (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) से पीड़ित 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांग कर्मचारी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इलाज पर खर्च हुए 3.95 लाख रुपये की मेडिकल प्रतिपूर्ति, पूरा वेतन, सेवा लाभ तथा कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमैरेरी (अतिरिक्त) पद सृजित करने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 13 अगस्त 2025 के बाद कर्मचारी द्वारा लिए गए बिना वेतन अवकाश को मेडिकल लीव माना जाए। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एएलएस जैसी तेजी से बढ़ने वाली गंभीर अपक्षयी बीमारी के मामलों में 'इमरजेंसी' की अवधारणा को

संकीर्ण नहीं, बल्कि व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

अदालत ने माना कि ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुनील कुमार वर्ष 2018 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए थे और वर्ष 2022 में सहायक पद पर पदोन्नत किए गए। बाद में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज (एएलएस) होने का पता चला। बीमारी के कारण उनके दोनों हाथ-पैरों ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांग घोषित किया गया।

बेहतर उपचार के लिए उन्होंने बेंगलुरु स्थित एक विशेषीकृत चिकित्सा केंद्र में स्टेम सेल थेरेपी सहित इलाज कराया, जिस पर लगभग 3.95 लाख रुपये खर्च हुए। हालांकि, शिक्षा बोर्ड ने यह कहते हुए मेडिकल प्रतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया कि उपचार आपातकालीन परिस्थितियों में नहीं कराया गया था।

रीडर भर्ती में 'विवा' के मनमाने अंकों पर हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक जवाब मांगा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में रीडर (लीगल) भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दो अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि लिखित परीक्षा सहित अन्य सभी निर्धारित चरणों में सफल होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार (विवा) में मनमाने ढंग से बेहद कम अंक दिए गए, जिसके कारण उनका अंतिम चयन नहीं हो सका। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिका में पिंजोर निवासी नीलम और एक अन्य अभ्यर्थी ने अंतिम चयन परिणाम के साथ-साथ उनकी आपत्तियों को खारिज करने वाले आदेशों को भी रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं रही तथा विवा के अंकों में मनमानी की गई। इससे योग्य अभ्यर्थियों को

लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों ने विवा अंकों को मनमाना बताते हुए हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा।

चयन सूची से बाहर कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. रावत ने अदालत को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को रीडर (लीगल) के 60 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा और अन्य चरण आयोजित किए गए, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक योग्यता प्राप्त की। इसके बाद हुए साक्षात्कार में उन्हें अपेक्षा से बहुत कम अंक दिए गए, जिससे वे अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि साक्षात्कार में अंक देने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और मूल्यांकन के लिए कोई स्पष्ट एवं समान मानक अपनाए जाने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसी आधार पर चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों से जवाब तलब करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 सितंबर निर्धारित की है।

अब अदालत के समक्ष दाखिल होने वाले जवाब और रिकॉर्ड के आधार पर यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई या नहीं। मामले की अगली सुनवाई पर अभ्यर्थियों और अन्य उम्मीदवारों की नजरें टिकी हुई हैं। यदि अदालत को प्रथम दृष्टया चयन प्रक्रिया में अनियमितता के पर्याप्त आधार मिलते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा, चयन परिणाम में संशोधन अथवा नए सिरे से साक्षात्कार कराने जैसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

आयुष विश्वविद्यालय ने निकाली 60 पदों पर वैकेंसी, अधिसूचना जारी

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय (एसकेएयू) ने नॉन-टीचिंग और पैरा-मेडिकल कैडर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 60 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध कराई गई है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञापन संख्या एनटी 01/2026 से 03/2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों में नॉन-टीचिंग स्टाफ और पैरा-मेडिकल कैडर के कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों और पात्रता मानकों के अनुसार संपन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले

अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव तथा अन्य आवश्यक शर्तों की जांच अवश्य कर लें। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी होगी, इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेज समय रहते तैयार रखने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती का उद्देश्य विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती पूरी होने के बाद संस्थान में कार्य व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी अपडेट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।

पर्ल ग्रुप जमीन मामले में नए साक्ष्यों के बाद विक्रम सिंगला दोबारा विजिलेंस की गिरफ्त में

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

हरियाणा के रायपुररानी स्थित पर्ल ग्रुप की करीब 50 एकड़ जमीन की कथित अनियमित बिक्री से जुड़े बहुचर्चित मामले में हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व तहसीलदार विक्रम सिंगला को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब विजिलेंस अदालत से उनका पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात विजिलेंस टीम ने विक्रम सिंगला को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किए जाने की तैयारी की गई, जहां जांच एजेंसी पुलिस रिमांड की मांग करेगी। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान जमीन की बिक्री, दस्तावेजों की प्रक्रिया और

50 एकड़ जमीन मामले में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

अन्य संबंधित पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

यह इस मामले में विक्रम सिंगला की दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले 31 जनवरी को हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उस समय पूछताछ के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आ गए थे। हालांकि, जांच आगे बढ़ने के दौरान एजेंसी को कुछ नए साक्ष्य और जानकारियां मिलीं, जिनके आधार पर दोबारा गिरफ्तारी की गई। विजिलेंस ब्यूरो की जांच रायपुररानी क्षेत्र में पर्ल ग्रुप की लगभग 50 एकड़ जमीन की कथित अनियमित बिक्री और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जमीन के लेनदेन में नियमों का पालन हुआ था या नहीं तथा किसी स्तर पर पद का दुरुपयोग या अनियमितता तो नहीं हुई।

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। विजिलेंस का कहना है कि पुलिस रिमांड मिलने के बाद विक्रम सिंगला से विस्तृत पूछताछ की जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले पर प्रशासनिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है, क्योंकि पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि पूछताछ और साक्ष्यों में नए तथ्य सामने आते हैं तो आगे और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बहादुरगढ़ से हरिद्वार तक 500 किमी साइकिल यात्रा, बीआरजी ने रचा नया कीर्तिमान

23 से 26 जुलाई तक चले अभियान में साइक्लिस्टों ने 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़

फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) साइक्लिंग ग्रुप के सदस्यों ने बहादुरगढ़ से हरिद्वार तक 500 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। साहस, अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए साइक्लिस्टों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस चुनौतीपूर्ण अभियान को पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।

यह विशेष अभियान 23 जुलाई की शाम बहादुरगढ़ से शुरू हुआ। यात्रा में शामिल सभी साइक्लिस्ट पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ निर्धारित मार्ग पर रवाना हुए। उन्होंने पूरे सफर के दौरान लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति बनाए रखी और लगातार पैडलिंग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अभियान का उद्देश्य केवल लंबी दूरी तय करना नहीं था, बल्कि लोगों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी था। यात्रा के दौरान साइक्लिस्टों को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

लंबे सफर, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, रातभर लगातार साइकिल चलाने और शारीरिक थकान के बावजूद किसी भी सदस्य ने हिम्मत नहीं हारी।

टीम ने शानदार तालमेल और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए करीब 16 घंटे में हरिद्वार पहुंचकर अपना लक्ष्य हासिल किया। वहां पहुंचने के बाद सभी सदस्यों ने मां गंगा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त कर अभियान की सफलता के लिए प्रार्थना की। हरिद्वार में कुछ समय विश्राम करने के बाद टीम ने वापसी की यात्रा शुरू की। वापसी के दौरान भी साइक्लिस्टों ने उसी अनुशासन और गति को बनाए रखा। लगभग 15 घंटे का सफर तय करने के बाद 26 जुलाई की सुबह पूरी टीम सुरक्षित बहादुरगढ़ लौट आई। इस प्रकार आने-जाने सहित 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर समूह ने अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और टीमवर्क का शानदार प्रदर्शन किया।

यात्रा का मार्ग बहादुरगढ़ से भिवानी, गोहाना, पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए हरिद्वार तक निर्धारित किया गया था। वापसी भी इसी मार्ग से की गई। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और साइक्लिंग प्रेमियों ने फूल-मालाओं के साथ साइक्लिस्टों का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने इस अभियान को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणादायक पहल बताते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस अभियान में बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप के साथ भिवानी साइक्लिंग कम्युनिटी (बीसीसी),

500 किलोमीटर अभियान पूरा कर साइक्लिस्टों ने युवाओं को किया प्रेरित

पेडल पल्स दिल्ली (पीपीडी) तथा आरपीएस साइक्लिंग ग्रुप के सदस्य भी शामिल हुए। विभिन्न शहरों के साइक्लिस्टों की भागीदारी ने इस अभियान को और अधिक प्रभावी तथा प्रेरणादायक बना दिया।

इससे यह संदेश भी गया कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। अभियान में जैदेव राठी, नितिन अत्री, अमित कादियान, मुकेश कुमार, कुमार गौरव, अजमेर हुड्डा, दीपक ग्रेवाल, शिवम भारद्वाज, राज प्रकाश, अनुज गोस्वामी, जितेंद्र पाल, नरेश शर्मा, नरेंद्र कुमार, प्रशांत शर्मा, सुबोध दुहान, पवन कौशिक, अंकुर अग्रवाल सहित अनेक साइक्लिस्टों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी प्रतिभागियों ने पूरे अभियान के दौरान अनुशासन, समर्पण और आपसी सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। बीआरजी साइक्लिंग ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग साइक्लिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

गुरुग्राम में पीजी दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, छात्रों को बड़ी राहत, 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

गुरुग्राम जिले के सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले जहां आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। इस फैसले से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे।

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थी अब 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर पहली मेरिट सूची 11 अगस्त को जारी की जाएगी। मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी कराई जाएगी।

इस बार जिले के सरकारी कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए पहले की तुलना में अधिक विषयों का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। कई कॉलेजों में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार विषय चुनने का बेहतर अवसर मिलेगा। विभाग का मानना है कि नए पाठ्यक्रम शुरू होने से उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी और उन्हें बेहतर शैक्षणिक विकल्प मिलेंगे। कॉलेज

पहली मेरिट सूची ग्यारह अगस्त को होगी जारी

प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन पत्र भरते समय सभी आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी जानकारी सही ढंग से अपलोड करने की सलाह भी दी गई है, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है। इससे किसी भी योग्य छात्र का दाखिला केवल समय की कमी के कारण प्रभावित नहीं होगा। विभाग को उम्मीद है कि बढ़ी हुई समय सीमा के बाद अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे और सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सकेगी।

गाजियाबाद में 400 करोड़ के कथित जमीन फर्जीवाड़े का मामला, चार बड़े बिल्डरों पर एफआईआर

भारतेंदु संवाददाता,चंडीगढ

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित 400 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में एनसीआर के चार बड़े बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई गौर बिल्डर ग्रुप की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता मनोज गौड़ ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने आपसी साठगांठ कर फर्जी कंपनियां बनाईं और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन की बिक्री और बैनामा प्रक्रिया को अंजाम दिया।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से चार फर्जी कंपनियों का गठन किया। इसके बाद कथित रूप से फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर जमीन से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा करने या अधिकार हासिल करने का प्रयास किया गया। मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में जमीन से जुड़े दस्तावेजों, कंपनियों के रिकॉर्ड और संबंधित लेन-देन की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित फर्जी कंपनियां कब और किस उद्देश्य से बनाई गईं तथा उनके माध्यम से किन गतिविधियों को अंजाम दिया गया। मामले में आरोप लगाए गए बिल्डरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। जमीन विवाद और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े इस मामले ने एनसीआर के बिल्डर जगत में चर्चा बढ़ा दी है। करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े इस प्रकरण में अब पुलिस की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, आरोपी पक्षों को भी जांच के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस का बयान दर्ज, शिकायत रसीद विवाद हुआ खत्म

भारतेंदु संवाददाता,चंडीगढ

दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित बल प्रयोग के मामले में पुलिस आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत की रसीद नहीं मिलने से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों के बयान को रिकॉर्ड करते हुए मामले को समाप्त किया। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था। इस संबंध में पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी गई थी, लेकिन शिकायत की प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई।

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि याची को शिकायत जमा करने की रसीद डीडी नंबर के साथ प्रदान की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के इस बयान को अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद शिकायतकर्ता को अब आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की मांग थी कि शिकायत को स्वीकार कर उचित जांच शुरू की जाए और कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

न्यूज ब्रीफ

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रेम विवाह में पुलिस हस्तक्षेप पर लगाई रोक

एजेंसी ,नई दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बालिग युवक-युवती को अपनी इच्छा से विवाह करने का पूरा अधिकार है। अपनी मर्जी से किया गया विवाह कोई अपराध नहीं है और ऐसे मामलों में पुलिस को बिना वजह हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने शुभांगी शुक्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता दंपती ने कोर्ट को बताया कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने अदालत से एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब दो वयस्क लोग अपनी सहमति से जीवनसाथी चुनते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई उचित नहीं है।

अलीगढ़ में 55 करोड़ की सड़कें फाइलों में कैद कार्यादेश का इंतजार

एजेंसी, नई दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास कार्यों को तेज करने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में प्रशासनिक देरी के कारण महत्वपूर्ण सड़क परियोजना अटक गई है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जिले में बनने वाली 112 ग्रामीण सड़कों का काम पिछले दो महीने से सरकारी फाइलों में रुका हुआ है। इन सड़कों के निर्माण के लिए करीब 55 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने में देरी हो रही है। मामले को लेकर अफसरशाही की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फाइनेंशियल डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यादेश जारी करने में देरी हो रही है। वहीं, शासन की मंशा है कि विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के निर्माण में देरी से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू कराता है। अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें।

सोनीपत में रोजगार की नई राह, पात्रों को 6 लाख रुपये तक का मिलेगा ऋण

एजेंसी, नई दिल्ली । सोनीपत में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक लाख रुपये से छह लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन सह अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की सीईओ डॉ. अनमोल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना के पात्र लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा। सीईओ डॉ. अनमोल ने बताया कि पीएम-अजय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को मिलने वाले ऋण पर सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।

प्रयागराज जंक्शन को मिली नई सौगात तिरुनेलवेली तक चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन

एजेंसी, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तक नई सुपरफास्ट/एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इस नई ट्रेन से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। नई ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को धार्मिक स्थलों, व्यापारिक केंद्रों और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

यह ट्रेन प्रयागराज से दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और समय बचाने वाला बनाएगी। रेल मंत्रालय की इस पहल से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्री अब दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता वाले क्षेत्रों तक सीधे पहुंच सकेंगे। इसके अलावा व्यापारियों और अन्य कामकाजी यात्रियों को भी इस ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा।

तिरुनेलवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से प्रयागराज सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दक्षिण भारत जाने के लिए एक नया विकल्प मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क बेहतर होगा। नई रेल सेवा को क्षेत्रीय विकास, पर्यटन विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उत्तर-दक्षिण भारत के बीच यात्रा और आसान होगी नई ट्रेन से पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा।

दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई चिंता, कई इलाकों में जलभराव की आशंका

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा रात के समय भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक, 4 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बारिश के दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते कई जगहों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग सतर्क

प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने और सुरक्षा के उपाय अपनाने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान जलभराव और यातायात संबंधी परेशानियों को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

रेवाड़ी में गरजे बिजली कर्मचारी, निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना का किया विरोध

एजेंसी, नई दिल्ली

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रेवाड़ी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की कर्मचारी विरोधी और बिजली क्षेत्र से जुड़ी नीतियों के कारण विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी के विरोध में राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेवाड़ी में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी शक्ति भवन परिसर में एकत्र हुए, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसके बाद कर्मचारियों ने शक्ति भवन से रोष मार्च निकाला, जो शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों से होकर जिला सचिवालय पहुंचा। वहां प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की गई।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार से कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, बिजली निगमों के निजीकरण और ठेकाकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि इन फैसलों से न केवल कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि बिजली सेवाओं की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा कर्मचारियों ने हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन, गुरुग्राम और नूंह में पैरलल लाइसेंस जारी करने, बिजली कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग और टीबीसीबी परियोजनाओं का भी विरोध जताया।

आगरा एयरपोर्ट का होगा विस्तार,बनेगा नया कार्गो टर्मिनल

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के पास एक अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई सुविधा से आगरा में सामान की हवाई आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने नए कार्गो टर्मिनल के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है। प्रस्तावित कार्गो टर्मिनल नए सिविल एन्क्लेव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इसके लिए करीब एक एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने टर्मिनल निर्माण का प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भेज दिया है। एएआई से मंजूरी मिलने के बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। कार्गो टर्मिनल बनने के बाद आगरा से व्यापारिक वस्तुओं, औद्योगिक उत्पादों और अन्य जरूरी सामान की हवाई परिवहन सुविधा बेहतर हो जाएगी।

गाजियाबाद में पत्नी पर पति को कुचलने की कोशिश का आरोप,पति ने दर्ज कराई शिकायत

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि दोनों ने मिलकर उसे कार से कुचलने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर थाने में पति-पत्नी के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मुरादनगर की एक कॉलोनी में रहने वाले युवक और उसकी पत्नी के बीच पिछले करीब दो वर्षों से विवाद चल रहा है। विवाद के चलते उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही है। युवक ने आरोप लगाया कि मंगलवार दोपहर वह किसी काम से बाइक द्वारा गाजियाबाद जा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने कार से उसका पीछा किया और उसे टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की। युवक का

मुरादनगर में पति का गंभीर आरोप, जांच शुरू

आरोप है कि किसी तरह उसने खुद को बचाया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद वह थाने पहुंचा, जहां पत्नी भी पहुंच गई। थाने में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और हंगामा चलता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और युवक की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

दिल्ली पुलिस की सख्ती, मानहानिकारक पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई

आपत्तिजनक पोस्ट करने से पहले सावधान! दिल्ली पुलिस की बड़ी चेतावनी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने, झूठी जानकारी फैलाने या अपशब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए हुए है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित होने वाले पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों की निगरानी की जा रही है। विशेष रूप से उन पोस्टों की जांच की जा रही है जिनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा, गाली-गलौज या झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कंटेंट को केवल साझा करने वाले ही नहीं, बल्कि उसे तैयार करने और प्रसारित करने वाले लोगों की भी पहचान की जाएगी। जांच एजेंसियां तकनीकी माध्यमों की सहायता से सोशल मीडिया अकाउंट, आईपी एड्रेस और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों से भी जानकारी मांगी जाएगी ताकि पोस्ट करने वाले व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा जा सके।

दिल्ली पुलिस का एक्शन, अभद्र पोस्ट करने वालों की खैर नहीं

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने या साझा करने से बचें। यदि किसी पोस्ट से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका होगी तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वही कानून लागू होते हैं जो वास्तविक जीवन में लागू होते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार और मर्यादित व्यवहार अपनाना चाहिए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। सोशल मीडिया पर जिम्मेदार व्यवहार अपनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

गुरुग्राम में बस रही है भविष्य की ग्लोबल सिटी, हाईटेक सुविधाओं से बदलेगी तस्वीर

एजेंसी, नई दिल्ली

हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी परियोजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजनाओं में शामिल है। यह आधुनिक शहर हाईटेक सुविधाओं, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ तैयार किया जाएगा। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे दो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक राज्य राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों तक तेज और सुगम आवागमन संभव होगा।

ग्लोबल सिटी को मिश्रित उपयोग वाले स्मार्ट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, होटल, स्वास्थ्य, मनोरंजन और हरित क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा। यहां स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, भूमिगत उपयोगिताएं, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, डिजिटल सेवाएं और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना का उद्देश्य गुरुग्राम को वैश्विक निवेश, कारोबार और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है। बेहतर सड़क नेटवर्क के साथ यह शहर द्वारका एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों से भी लाभान्वित होगा, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को नई गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही है और इससे आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ग्लोबल सिटी के विकसित होने के बाद गुरुग्राम की पहचान केवल कॉर्पोरेट हब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आधुनिक शहरी विकास और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रीय स्तर पर एक नया उदाहरण भी बनेगा।

ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फरार बदमाश को दबोचा

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस को उसकी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी एक रिहायशी सोसाइटी में छिपकर रह रहा है और बाहर निकलने से भी बच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सोसाइटी के आसपास निगरानी बढ़ा दी। कई घंटों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, पुलिस ने उसे घेर लिया। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया, लेकिन पूछताछ में उसकी पहचान की पुष्टि हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर केंद्र से की सक्रियता की अपील

गुलाम जम्मू-कश्मीर के हालात पर चुप न रहे सरकार : फारूक अब्दुल्ला

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार से गुलाम जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोगों के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार गुलाम जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानती है तो वहां के हालात और लोगों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज स्पष्ट रूप से उठानी चाहिए।

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों की स्थिति और उनकी चिंताओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वहां होने वाले घटनाक्रम पर भारत सरकार को अपना पक्ष दुनिया के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रभावी आवाज सुनाई नहीं दी है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से भी अपील की कि वह गुलाम जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों की स्थिति और वहां के घटनाक्रम का संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

एनसी अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं का समाधान होने तक इस विषय पर लगातार और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाए और संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए।

फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उनके मुद्दों को उचित मंचों पर उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान संभव है। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से शांति और जनहित को प्राथमिकता देने की अपील की।

> **उन्होंने** दिल्ली में छात्रों से जुड़े मामलों में परिवारों को परेशान किए जाने के आरोपों पर भी चिंता जताई। सरकार को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए सरकार को संतुलित नीति बनानी चाहिए। ताकि विकास के साथ नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो सके।

होटल विवाद

जम्मू-कश्मीर में अवैध होटलों के निर्माण को लेकर चल रही बहस के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने निजी होटल क्षेत्र का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में होटल बनना पर्यटन विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों का संकेत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा प्रदेश में 5,000 से अधिक अवैध होटलों के निर्माण का जिक्र किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ठहरने की सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पहले पर्यटकों को कई बार रहने की जगह नहीं मिलती थी।

महबूबा ने फल आपूर्ति के लिए आपात परिवहन व्यवस्था की मांग की

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार आ रही बाधाओं को देखते हुए कश्मीर के बागवानी उत्पादों की समय पर निकासी के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क प्रभावित होने से फल उत्पादकों को भारी नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि कश्मीर में फल उत्पादन का मौसम बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस समय बागवानों की पूरी मेहनत बाजार तक पहुंचने पर निर्भर करती है। उन्होंने चिंता जताई कि लंबे समय तक सड़क बंद रहने से सेब सहित अन्य नाशवान फलों की गुणवत्ता खराब हो सकती है और उत्पादकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि फलों से भरे कई ट्रक सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिससे बागवानों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।

सुरक्षाबलों की सतर्कता से टली बड़ी आतंकी साजिश

कुलगाम में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करके हथियारों का जखीरा किया बरामद

भारतेंदु संवाददाता, कुलगाम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए हथियारों और गोला-बारूद का भारी जखीरा बरामद किया है। यह कार्रवाई जिले के तांत्रेपोरा-सुरसनू इलाके में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान की गई।

जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि तांत्रेपोरा-सुरसनू के घने बाग वाले क्षेत्र में संदिग्ध सामग्री छिपाई गई है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया।

कुलगाम पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने मिलकर क्षेत्र की घेराबंदी की। अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को छिपाकर रखे गए हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, बरामद किए गए सामान की जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसे किस उद्देश्य से वहां छिपाया गया था।

एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि इस सामग्री के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसका इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात के लिए तो नहीं किया जाना था।

सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान को आगे भी जारी रखा है, ताकि किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि या छिपे हुए सामान का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

इस सफल अभियान को सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल और समय पर मिली खुफिया जानकारी का परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।

बाग के चप्पे-चप्पे में चला सर्च ऑपरेशन

कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। तांत्रेपोरा-सुरसनू के बाग क्षेत्र में बुधवार सुबह से चलाए गए अभियान में जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर गहन जांच की। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षाबलों को बाग के अंदर छिपाकर रखे गए हथियार मिले। बरामद सामान में दो पिस्तौल, दो राइफल और सात ग्रेनेड सहित अन्य सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों और गोला-बारूद को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह हथियार किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं और इन्हें किसने छिपाया था।

अमरनाथ यात्रा के 22वें जत्थे में 2,051 लोग कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 22वां जत्था बुधवार तड़के जम्मू से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह करीब 2:45 बजे 2,051 तीर्थयात्रियों का जत्था बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस जत्थे को 82 वाहनों के काफिले में भेजा गया। इसमें 48 बसें, आठ मध्यम मोटर वाहन, 25 छोटे वाहन और एक दोपहिया वाहन शामिल था। सुरक्षा बलों ने पूरे मार्ग पर विशेष निगरानी रखी और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। इस जत्थे में 1,570 पुरुष श्रद्धालु, 369 महिलाएं, दो बच्चे, 58 साधु, 21 साध्वियां, एक साधु बच्चा और 30 विदेशी नागरिक शामिल हैं। विदेशी श्रद्धालुओं में 14 पुरुष और 16 महिलाएं हैं। सभी श्रद्धालु बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते पहलगाम मार्ग से इस जत्थे के लिए कोई काफिला निर्धारित नहीं किया गया था।

दक्षिण कश्मीर के आस्था केंद्र खू साहिब चश्मे का होगा कायाकल्प, सरकार ने खोला 6.38 करोड़ का खजाना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने धार्मिक और विरासत स्थलों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने पुलवामा जिले के शादीमार्ग स्थित यारवन के पवित्र खू साहिब चश्मे के विकास के लिए 6.38 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है।

इस परियोजना के तहत तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों को सुविधाजनक अनुभव मिल सके। इसके साथ ही स्थल के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू ने निजी स्कूलों पर एडमिशन फीस वसूलने का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने कई निजी स्कूलों पर सरकार के आदेशों की अनदेखी कर अभिभावकों से एडमिशन फीस वसूलने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जब सरकार ने एडमिशन फीस लेने पर रोक लगाई है, तो इसके बावजूद स्कूलों द्वारा फीस क्यों ली जा रही है। उन्होंने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और मामले की जांच की मांग की। अमित कपूर ने सरकार से अपील की कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके।

सांबा में बाइक टक्कर से पैदल यात्री की मौत

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। सांबा जिले के एसआईडीसीओ इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को मोटरसाइकिल की टक्कर से एक पैदल यात्री की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया, जहां से पैदल यात्री को गंभीर हालत में एम्स विजयपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नेपाल निवासी चंद्रपाल के बेटे राजू के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल सवार भी घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले को सजा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने फर्जी 10+2 प्रमाण पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व पुलिस (आईआरपी) की 9वीं बटालियन में कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है। मामले में श्रीनगर स्थित विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट अदालत ने कुपवाड़ा निवासी नजीर अहमद मलिक को दोषी करार दिया है। जांच के दौरान उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जब्त कर जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां इसे फर्जी पाया गया। अदालत ने आरोपी को धारा 420 आरपीसी के तहत तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 471 आरपीसी के तहत दो साल के साधारण कारावास की सजा भी दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ईओडब्ल्यू ने लोगों से अपील की है कि रोजगार या सरकारी कार्यों के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है।

ऑपरेशन कामधेनु में पुलिस ने बचाए 81 गोवंशीय पशु

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत गोवंश तस्करी के तीन प्रयास विफल करते हुए 81 पशुओं को सुरक्षित बचाया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल तीन वाहनों को भी जब्त किया। सिद्धड़ा ब्रिज, बन टोल और नधाल में हुई कार्रवाई के दौरान एक चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने संबंधित थानों में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जम्मू में तेज रफ्तार मेटाडोर पलटी, नौ लोग घायल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। मुट्ठी स्थित ड्रीम सिटी के पास बुधवार को तेज रफ्तार मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे नौ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है। घायलों में विक्रम, सुबी, रजनी, रिंकू, इश्लाक हुसैन, इरफान, अवंतिका, साहिल सिंह और रिया शर्मा शामिल हैं।

जम्मू में 80 साल पुराना मकान ढहा, बंद हुई गली नगर निगम मालिक से वसूलेगा मलबा हटाने का खर्च

जर्जर इमारतों पर कार्रवाई की तैयारी में नगर निगम

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल मल्होत्रा मुहल्ले में बुधवार सुबह एक पुराने मकान का जर्जर हिस्सा अचानक ढह गया। हालांकि, हादसे के समय गली में लोगों की आवाजाही कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जब करीब 80 साल पुरानी इमारत का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गया।

इमारत गिरने से करीब छह फुट चौड़ी गली पूरी तरह मलबे से बंद हो गई। अचानक हुई इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गली के सामने कई दुकानें भी मौजूद थीं, जिससे स्थिति को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में आवाजाही रोक दी।

इसके बाद जम्मू नगर निगम की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। निगम कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मलबा हटाने का काम शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद बंद पड़ी गली को दोबारा यातायात और पैदल आवाजाही के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर संजय बड़याल ने बताया कि राहत और सफाई कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुरानी इमारत वर्तमान में गोदाम के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

बडगाम में सीआरपीएफ वाहन के पेड़ से टकराने से तीन जवान घायल, एक की हालत गंभीर

शेखपोरा हादसे में घायल जवान अस्पताल में भर्ती

भारतेंदु संवाददाता, बडगाम। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए। हादसा शेखपोरा इलाके के पास हुआ, जहां सीआरपीएफ का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक विशाल चिनार के पेड़ से टकरा गया।

जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ का वाहन नियमित ड्यूटी के दौरान शेखपोरा क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन तेज रफ्तार से पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार, हादसे में घायल तीनों जवानों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर के अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, अन्य दो जवानों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

हादसे के बाद यातायात पूरी तरह बहाल

हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

अब जम्मू में होगी मखाने की खेती, कृषि एक्सपर्ट्ज ने दिए कमाई बढ़ाने के मंत्र

मखाना उत्पादन की संभावनाओं पर हुआ मंथन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू। जम्मू क्षेत्र में अब मखाना खेती को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए तालाब तिल्लो स्थित कृषि भवन में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर में मखाना खेती की संभावनाओं और इससे जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सेमिनार का शुभारंभ कृषि निदेशक अनिल गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और मखाना खेती से जुड़े किसानों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने किसानों को मखाना उत्पादन की तकनीक, खेती के लिए जरूरी परिस्थितियों और इससे होने वाले आर्थिक लाभों की जानकारी दी।

विशेषज्ञ डॉ. इंदू शेखर सिंह ने बताया कि मखाना पानी में उगने वाले पौधे का बीज है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। उन्होंने मखाना खेती के लिए उपयुक्त वातावरण, पौध तैयार करने, फसल प्रबंधन और कटाई की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में मखाना की अधिकांश खेती बिहार में होती है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में भी इसकी खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। यहां के कुछ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और मौसम इस फसल के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

जीआई टैग से हिमालयी उत्पादों को मिलेगी नई उड़ान

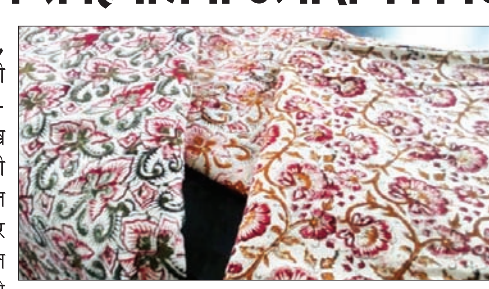

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। हिमालय की गोद में बसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत अब वैश्विक मंच पर नई पहचान हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्षेत्र के 32 पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जीआई टैग मिलने के बाद इन उत्पादों की भौगोलिक पहचान सुरक्षित होगी और स्थानीय कारीगरों, किसानों तथा पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को देश-विदेश के बाजारों में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

इस सूची में सांबा की प्रसिद्ध कैलिको छपाई कला और किश्तवाड़ की पाडर घाटी का दुर्लभ नीला नीलम प्रमुख रूप से शामिल हैं। सांबा की कैलिको प्रिंटिंग डोगरा क्षेत्र की पुरानी हस्तकला परंपरा का हिस्सा रही है। सूती कपड़े पर लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉकों से प्राकृतिक रंगों की मदद से फूलों, ज्यामितीय आकृतियों और पारंपरिक डिजाइनों की छपाई की जाती है। हालांकि मशीन से बने कपड़ों के बढ़ते चलन के कारण यह कला धीरे-धीरे कमजोर हुई, लेकिन जीआई टैग मिलने की उम्मीद से इसके पुनर्जीवन की संभावनाएं बढ़ी हैं। वहीं, किश्तवाड़ की पाडर घाटी से निकलने वाला नीला नीलम अपनी दुर्लभ गुणवत्ता, चमक और गहरे रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जीआई पहचान मिलने से इसकी प्रमाणिकता सुरक्षित होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ने की संभावना है।

◆ **32 उत्पादों को जीआई टैग मिलने से कारीगरों और किसानों को मिलेगा लाभ**

अधिकारियों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के 26 और लद्दाख के छह उत्पाद जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। इनमें कृषि उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्रीय विकास मुद्दों पर की चर्चा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के कई विधायकों ने बुधवार को श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जन समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

◆ **विधायकों ने रखीं जनसमस्याएं, मुख्यमंत्री ने समाधान का दिया भरोसा**

मुख्यमंत्री से मिलने वाले विधायकों में कठुआ के विधायक डॉ. भरत भूषण, कलाकोट-सुंदरबनी के विधायक रणधीर सिंह, किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार, उड़ी के विधायक डॉ. सज्जाद शफी, लोलाब के विधायक जमशेद लोन, कंगन के विधायक मियां मेहर अली और तंगधार के विधायक जावेद मिर्चाल शामिल रहे। इसके अलावा पूर्व एमएलसी अधिवक्ता रतन लाल गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

बैठकों के दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

फिल्मोत्सव पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दुनिया भर के फिल्मकारों की भागीदारी, 875 फिल्मों की मिलीं प्रविष्टियां

जम्मू-कश्मीर फिल्म महोत्सव को वैश्विक पहचान, 50 देशों से मिली फिल्में

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पहली बार आयोजित होने जा रहे जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफजेके)-2026 को लेकर दुनियाभर के फिल्मकारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस महोत्सव के लिए अब तक करीब 50 देशों से 875 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में आई इन प्रविष्टियों ने आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है। आयोजकों के अनुसार, विभिन्न देशों से भेजी गई फिल्मों में अलग-अलग विषयों, संस्कृतियों और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

फिल्म महोत्सव के लिए प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके बाद विशेषज्ञों की चयन समिति फिल्मों का मूल्यांकन करेगी और महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों का चयन किया जाएगा। चयनित फिल्मों को सितंबर में आयोजित होने वाले महोत्सव के दौरान दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह महोत्सव सात से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश-विदेश के फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और फिल्म प्रेमी जम्मू-कश्मीर में एकत्र होंगे।

फिल्म हब बनने की राह पर जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, देश-विदेश से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि प्रदेश अब पर्यटन के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों और फिल्म उद्योग के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। करीब 50 देशों से आई फिल्मों की प्रविष्टियां महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेंगी। चार दिवसीय आयोजन में फिल्मों की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञों के संवाद, मास्टर क्लास, परिचर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

महोत्सव का उद्देश्य

फिल्म महोत्सव का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पहुंचाना है। इसके जरिए बेहतरीन फिल्मों को प्रोत्साहित करने, विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों के बीच संवाद बढ़ाने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया था। उन्होंने देश-विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों, निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों से इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने की अपील की थी।

न्यूज ब्रीफ

9.05 ग्राम चिट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और सफलता हासिल की है। स्पेशल डिटेक्शन टीम ने 27 जुलाई को पट्टा चौक फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार से 9.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस के अनुसार, किरतपुर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर चालक अजय ठाकुर (32) निवासी बैहल कंडैला, डाकघर बामटा, बिलासपुर के कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लाया था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ तस्करी सहित कई मामले दर्ज हैं।

राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में बुधवार को जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने जिले में लंबित राजस्व मामलों की उपमंडलवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निशानदेही, नामांतरण, बंटवारा और अन्य मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने छह माह और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाएं सरल, पारदर्शी और जनहितकारी होनी चाहिए। साथ ही सरकारी भूमि, चरागाहों और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित मामलों की प्रगति, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

प्रेम कुमार धूमल से मिले भाजपा नेता, लिया आशीर्वाद

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय बहल, वीरेंद्र ठाकुर, पवन शर्मा, तिलक राज बहल, चमन ठाकुर, रमेश चौहान, हरनाम सिंह, अजय रिंकू सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर नेताओं ने प्रो. धूमल को अपना मार्गदर्शक व गुरु मानते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। गुरु पूर्णिमा के महत्त्व पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है। गुरु ही अपने अनुभव, ज्ञान और संस्कारों से व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रो. धूमल के नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा की भावना से उन्हें निरंतर प्रेरणा मिलती रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनका मार्गदर्शन भविष्य में भी कार्यकर्ताओं को समाज एवं संगठन की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर सभी ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए समाज में गुरु-शिष्य परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने का संदेश भी दिया।

एग्री मशीनरी पोर्टल 31 जुलाई से होगा शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के तहत किसान अनुदान पर पावर टिलर, पावर वीडर सहित अन्य कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए पोर्टल 31 जुलाई, 2026 से सक्रिय होगा और किसान 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। 21 अगस्त को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल ही खरीदें। आधुनिक मशीनों के उपयोग से खेती की लागत कम होने और उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी।

वेव्स फिल्म बाजार स्क्रीनराइटर्स लैब के लिए आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वेव्स फिल्म बाजार स्क्रीनराइटर्स लैब-2026 के लिए भारतीय पटकथा लेखकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल के तहत आयोजित इस लैब का उद्देश्य फीचर फिल्म पटकथा लेखकों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन देकर उनकी कहानियों को बेहतर और बाजार के अनुरूप विकसित करना है। चयनित लेखकों को देश-विदेश के अनुभवी स्क्रिप्ट मेंटर्स के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागियों को पटकथा विकास, फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसर्स से संवाद तथा उद्योग से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। चयनित प्रतिभागी वेव्स फिल्म बाजार में अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे। लैब का पहला पांच दिवसीय आवासीय सत्र अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में मुंबई में होगा, जबकि ऑनलाइन मेंटरशिप सत्र अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। अंतिम 10 दिवसीय सत्र 15 से 24 नवंबर 2026 तक गोवा में होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 है। इच्छुक लेखक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।

सुनील बिट्टू ने डूग्घा में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने डूग्घा के गांव बसंदेहड़ा (लाहड़) का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने उनके समक्ष सड़क, पेयजल, हैंडपंप और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखीं। सुनील शर्मा बिट्टू ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद गांव की सड़क को पक्का करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही हैंडपंप के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और रिपोर्ट सही आने पर इसे विद्युत मोटर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

प्रदेश में तीन वर्षों में खनिजों से प्राप्त राजस्व में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री सुक्खू

अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में लगभग 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उद्योग विभाग के तहत खनन विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिज और लघु खनिजों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 340 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा हिमाचल से परिवहन होने वाले लघु खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, जिससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से खनिजों के बाहर भेजने की मात्रा में कमी होने के कारण राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने विभाग को इस मामले को पड़ोसी राज्यों से विधिपूर्वक उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने चूना पत्थर की रॉयल्टी की दरें संशोधित नहीं की हैं, इससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अपना वाजिब हक प्राप्त करने के लिए इस मामले को प्रमुखता से उठायेगा।

सुक्खू ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रदेश में खनिजों का दोहन वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलने चाहिएं तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों, नालों, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खनन केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही किया जाए तथा संबंधित एजेंसियां नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियां निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन डॉ. सुशील कुमार सिंगला, निदेशक उद्योग विवेक भाटिया, संयुक्त सदस्य सचिव हिमकोस्ट डॉ. सुरेश चंद अत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल में हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 369.82 एकड़ भूमि लंबित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क, एयरपोर्ट विस्तार व हेलिपोर्ट विकास से जुड़े मुद्दे उठाए जाने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में नागरिक उड्डयन ढांचे को सुदृढ़ बनाने और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में शिमला हवाई अड्डा दिल्ली व धर्मशाला, कांगड़ा (गगल) हवाई अड्डा दिल्ली, जेवर, चंडीगढ़ तथा शिमला, जबकि कुल्लू-भुंतर हवाई अड्डा अमृतसर, दिल्ली व जयपुर से जुड़ा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने योजना तैयार कर ली है, जिसके लिए 369.82 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन अभी तक एएआई को हस्तांतरित नहीं की गई है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016 के तहत विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कुल्लू-भुंतर व शिमला एयरपोर्ट के विस्तार में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और भूमि संबंधी सीमाएं प्रमुख बाधाएं हैं। वहीं, उड़ान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 40 हवाई मार्ग शुरू किए जा चुके हैं। वर्तमान में रामपुर, मंडी, रिकांगपिओ और संजौली से हेलिकॉप्टर सेवाएं संचालित हो रही हैं। हेलिपोर्ट अवसंरचना के लिए 51.11 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 37.31 करोड़ खर्च हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक पर्वतीय और आकांक्षी क्षेत्रों में 200 हेलिपोर्ट विकसित करने के लिए 3,661 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में हवाई संपर्क और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा राज्य सरकार को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक भूमि शीघ्र उपलब्ध करानी चाहिए।

जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में एडीसी ने दिए निर्देश

फील्ड में लगातार सैंपलिंग-टेस्टिंग करें खाद्य आपूर्ति अधिकारी

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एडीसी अभिषेक गर्ग ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फील्ड में लगातार सैंपलिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि जिला में उचित मूल्य की सभी 320 दुकानों में शिकायत नंबर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग खाद्यान्नों की गुणवत्ता या उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी की तुरंत शिकायत कर सकें। एडीसी ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान जिला में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों के 3421 निरीक्षण किए गए और इनसे 75 सैंपल लिए गए। इनमें से केवल एक सैंपल फेल हुआ। इसके अलावा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी 2089 निरीक्षण किए गए हैं और इनमें से 5 मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 9252 रुपए जुर्माना वसूला गया है। एडीसी ने बताया कि जिला के कुल 1,53,647 राशन कार्डों के 5,48,675 उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,63,150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला में सभी राशनकार्ड धारकों की आधार एवं मोबाइल की सीडिंग हो चुकी है। 96 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी हो चुकी है। जिले में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों और आवेदनों पर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों और पात्र आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति की सदस्य सचिव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक रीटा कुमारी, भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हिमाचल में 11,835 घरों पर लगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, 87 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति, केंद्रीय सहायता और हिमाचल प्रदेश में इसके क्रियान्वयन को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येस्सो नाइक ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मंत्री के अनुसार, फरवरी 2024 से 27 जुलाई 2026 तक देशभर में 40,45,298 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 48,80,796 परिवार लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 27,343.90 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 11,835 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे 11,868 परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य को 87 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। जिला स्तर पर सबसे अधिक संयंत्र कांगड़ा (2,306) और हमीरपुर (2,281) में लगाए गए हैं। इसके अलावा मंडी, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, चंबा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति में भी योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आवेदन से लेकर सब्सिडी वितरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और सभी दस्तावेज सही होने पर औसतन 15 दिनों के भीतर सब्सिडी लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है। योजना को सरल बनाने के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया आसान की गई है, 10 किलोवाट तक ऑटो लोड एन्हांसमेंट, बिना गारंटी रियायती ऋण, प्रशिक्षित विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि तथा जागरूकता और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

दसवीं की टॉपर अनीषा ने धर्माणी से की मुलाकात

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रदेशभर में दूसरा स्थान हासिल करने वाली छात्रा अनीषा महाजन ने बुधवार को घुमारवीं में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से भेंट की।

अनीषा महाजन ने 700 में से 698 अंक प्राप्त कर मैरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर मंत्री राजेश धर्माणी ने अनीषा को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्रा को इसी तरह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राजेश धर्माणी ने अनीषा की सफलता का श्रेय उसके परिश्रम के साथ-साथ विद्यालय के शिक्षकों, प्रबंधन और अभिभावकों के सहयोग को भी दिया तथा सभी को शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने घुमारवीं में किया भवानी ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में भवानी ई-लाइब्रेरी का विधिवत शुभारंभ किया।

भवानी ई-लाइब्रेरी में युवाओं को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतरीन वातावरण की सुविधा प्राप्त होगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि इस ई-लाइब्रेरी में एक समय में लगभग 100 विद्यार्थी बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां 24 घंटे हाई-स्पीड वाई-फाई उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त पूरी लाइब्रेरी को पूर्णत: वातानुकूलित (एयर कंडीशंड) बनाया गया है, ताकि सभी मौसम में विद्यार्थी आरामदायक वातावरण में पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में इस प्रकार की आधुनिक ई-लाइब्रेरी शुरू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। भवानी ई-लाइब्रेरी के माध्यम से जहां विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा तो वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। ई-लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भवानी ई-लाइब्रेरी क्षेत्र के अधिक से अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर ई-लाइब्रेरी के संचालक मंजीत कुमार, रितेश, बस यूनियन के प्रधान अनिल मिंटू अभिभावक, विद्यार्थी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

अक्षय ने एचपी सेट में हासिल की सफलता

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। ग्राम पंचायत ननांवां के होनहार छात्र अक्षय कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (एचपी सेट-2026) में कॉमर्स विषय में सफलता प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अक्षय कुमार ने वर्ष 2025 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर से एमकॉम की पढ़ाई के दौरान प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट जेआरएफ (कॉमर्स) परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उनका चयन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में कॉमर्स विषय में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के रूप में हुआ, जहां वे वर्तमान में शोध कार्य कर रहे हैं। अक्षय के पिता रमेश कुमार किसान परिवार से हैं और बद्दी में कार्यरत हैं, जबकि माता सरिता देवी गृहिणी हैं। उनकी सफलता पर परिजनों, गुरुजनों और ग्रामीणों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

जिला शतरंज प्रतियोगिता में प्रताप वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

वंशिका गुप्ता ने जीता स्वर्ण पदक

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। प्रताप वर्ल्ड स्कूल, पठानकोट के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पठानकोट डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला शतरंज प्रतियोगिता में शानदार सफलता हासिल की। प्रतियोगिता में विद्यालय के 39 विद्यार्थियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लेकर अपनी रणनीतिक सोच, धैर्य और एकाग्रता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में वंशिका गुप्ता ने अंडर-19 गर्ल्स वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मानस्वी ने अंडर-13 गर्ल्स वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया। अंडर-13 ब्वॉयज वर्ग में तेजेश्वर चौथे और अनिरुद्ध पांचवें स्थान पर रहे। आरव महाजन को कम आयु में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'यंगेस्ट प्लेयर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य विद्यार्थियों में वंश स्पोलिया, क्षितिज, पीयूष, भुनीश्वर, रेहान, राजबीर सिंह, करणजीत सिंह, उमंग पांडे, अपराजित कलंदरी, आरव शर्मा, गौरांग अटारी, अभिनव पठानिया, अथर्व, गौरीश शर्मा, रुद्रांश कटाल, अध्विक महाजन, माधवेश्वर, मिथिलेश्वर, शीरन, अहंवीर सिंह, हार्दिक बलोरिया, माधव सरीन, हिमांक दिक्षाल, अस्मी गुप्ता, हफ्ज़ा नूरीन खान, लविशा, आतिफा फातिमा, गुनतास, ओमेहरा, दिव्यांशी ठाकुर, ईशानवी, सान्वी और ऑरा शामिल रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्या सुभ्रा रानी ने सभी विजेता व प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शतरंज विद्यार्थियों में धैर्य, तार्किक सोच, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। विद्यालय के निदेशक सनी महाजन ने कहा कि प्रताप वर्ल्ड स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि जिला शतरंज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन विद्यालय की समग्र शिक्षा प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का परिणाम है। उन्होंने सभी विजेताओं, प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का पुनर्गठन, समर चौहान बने अध्यक्ष

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक शिमला में चुनाव अधिकारी जिया लाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से समिति का पुनर्गठन करते हुए आगामी कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

बैठक में समर चौहान को समिति का अध्यक्ष चुना गया, जबकि हरीश पराशर को उपाध्यक्ष, खेमेंद्र गुप्ता को सचिव, हरी कृष्ण को प्रवक्ता और राजेश ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा परिवहन कर्मचारी महासंघ (इंटक), तकनीकी कर्मचारी संगठन, एटक, परिवहन मजदूर संघ, चालक-परिचालक संगठन, सर्व कर्मचारी यूनियन, मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, निरीक्षक स्टाफ एसोसिएशन और स्टोर स्टाफ एसोसिएशन सहित सभी संबद्ध कर्मचारी संगठनों द्वारा नामित चार-चार मुख्य पदाधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के सदस्य होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों, सेवा हितों, कर्मचारी कल्याण, निगम के सुदृढ़ीकरण और जनहित से जुड़े परिवहन मामलों को सरकार तथा निगम प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएगी। नई कार्यकारिणी ने सभी कर्मचारी संगठनों से आपसी समन्वय, एकता और सहयोग की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। समिति ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी संगठनों को मिलकर प्रयास करना होगा। बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार नई कार्यकारिणी की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन, प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।

खुलासे ऐप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे जासूस, पाकिस्तान से दुबई तक फैला था जाल

जासूसी के लिए पैसों के साथ आईएसआई देती थी ड्रग्स

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के लिए कथित तौर पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी साझा करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सेना की रणनीतिक गतिविधियों की लाइव सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान स्थित हैंडलरों तक पहुंचाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को गोपनीय सूचनाओं के बदले केवल नकद राशि ही नहीं, बल्कि ड्रग्स भी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे बेचकर वे अतिरिक्त कमाई करते थे। एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान के साथ-साथ दुबई में बैठे हैंडलरों से भी जुड़े हुए थे। आरोपी सामान्य फोन कॉल या व्हाट्सऐप के बजाय एक विशेष एन्क्रिप्टेड एप के माध्यम से संपर्क में रहते थे, ताकि उनकी गतिविधियों का आसानी से पता न चल सके। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उस एप का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बीतू को जब कार्रवाई की भनक लगी, तो उसने जासूसी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन अपने बड़े भाई हरदीप सिंह को दे दिया। हरदीप ने कथित तौर पर सबूत मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद कर लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आया है कि सुजानपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच स्थित एक दुकान में इस तरह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे कि वहां से गुजरने वाले सेना और अर्धसैनिक बलों के काफिलों की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें। इन कैमरों की लाइव फीड इंटरनेट के माध्यम से कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलरों तक पहुंचाई जाती थी। इस मामले में पुलिस अब तक बलजीत सिंह उर्फ बीतू, अंकित शर्मा, हरदीप सिंह, बलजिंदर सिंह उर्फ विक्की और तरनप्रीत सिंह उर्फ तन्नू सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस का दावा है कि इनमें से कुछ आरोपी पहले से ही आईएसआई के संपर्क में थे और नेटवर्क को संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। यह मामला 21 मई को सुरक्षा एजेंसियों से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर सुजानपुर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने अब तक कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां सीमा पार भेजीं, उन्हें कितना आर्थिक लाभ मिला और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका रही। पुलिस का मानना है कि आगे की पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं तथा इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

हिमाचल की दो सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से 239 करोड़ रुपए मंजूर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए 239.45 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिली है। यह मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य की दो महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन परियोजनाओं के लिए दी है।

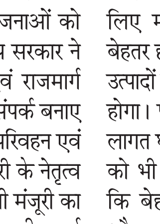

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी का स्वागत किया। मंजूर की गई परियोजनाओं में छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपए और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए 35.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का 16 किलोमीटर हिस्सा पहले स्वीकृत पैकेज में शामिल नहीं हो पाया था। अब इस हिस्से को मंजूरी मिलने से पूरी सड़क का काम पूरा हो सकेगा। इससे खासकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। उन्होंने कहा कि छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। सड़क के बेहतर होने से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। परिवहन में कम समय लगेगा, लागत घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से किसानों और बागवानों की बाजार तक पहुंच बढ़ेगी व फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करेगी।

पॉलीन की खूबसूरती के आगे एक्ट्रेस भी फेल

जर्मनी। पॉलीन शेफर-बेट्ज जर्मनी की प्रसिद्ध कलात्मक जिम्नास्ट हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1997 को हुआ था। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। बैलेंस बीम स्पर्धा में उनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं।

एशियाई खेलों के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, हरमनप्रीत बने कप्तान

एजेंसी, नई दिल्ली

हॉकी इंडिया ने बुधवार को जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेल-2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी स्टार डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ हरमनप्रीत सिंह करेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह टीम के उपकप्तान होंगे।

भारत मौजूदा एशियाई खेल चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। इस बार भी टीम का लक्ष्य खिताब बचाने के साथ-साथ लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक का सीधा कोटा हासिल करना होगा।

गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे। रक्षापंक्ति में जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं। मिडफील्ड में राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा और विवेक सागर प्रसाद टीम की कमान संभालेंगे। वहीं आक्रमण की जिम्मेदारी दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक के कंधों पर होगी। भारतीय टीम को पूल-ए में मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 22 सितंबर को श्रीलंका, 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया, 26 सितंबर को जापान और 28 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम चयन पर कहा कि यह बेहद अनुभवी टीम है और सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उन्हें टीम के हर खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन टीम की सबसे बड़ी ताकत है। खिलाड़ियों को बिना दबाव के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 90 रन से हराया

एजेंसी, तारौबा (त्रिनिदाद)

जाडेन सील्स के पांच विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 90 रन से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। पहली पारी में 311 रन बनाने वाली वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 181 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 211 रन का लक्ष्य रखा लेकिन उसकी टीम केवल 120 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान में पहली पारी में 282 रन बनाए थे।

पाकिस्तान की दूसरी पारी में केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें कप्तान बाबर आजम ने नाबाद 58 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कोर एक समय नौ विकेट पर 79 रन था। बाबर ने इसके बाद 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास (23) के साथ आखिरी विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हुआ। सील्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 20 रन देकर पांच विकेट लिए। केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। बाबर ने कहा, ''हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आज बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।'' दूसरा और अंतिम टेस्ट में रविवार से खेला जाएगा।

स्पोर्ट्स विंडो

टेन डोशेट बने कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेट रणनीतिकार

एजेंसी, कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स ने अपने पूर्व खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्य रहे रयान टेन डोशेट को हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी नियुक्त किया है। नई भूमिका में वह नाइट राइडर्स समूह की सभी वैश्विक फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट रणनीति, प्रतिभा पहचान, खिलाड़ी भर्ती और विकास योजनाओं का नेतृत्व करेंगे। टेन डोशेट स्काउटिंग, खिलाड़ी चयन, टीम संयोजन और प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़ी रणनीतियां तैयार करेंगे। वह विभिन्न फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर पूरे नाइट राइडर्स नेटवर्क में एक समान क्रिकेट दर्शन और कार्यशैली विकसित करने पर भी काम करेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ वह त्रिनबागो नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स और लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के सहायक कोच की भूमिका भी निभाएंगे। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर ने कहा कि रयान की क्रिकेट समझ और अंतरराष्ट्रीय व फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि टेन डोशेट के नेतृत्व से नाइट राइडर्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। अपनी नियुक्ति पर रयान टेन डोशेट ने खुशी जताते हुए कहा कि वह दोबारा नाइट राइडर्स परिवार से जुड़कर उत्साहित हैं।

विश्व कप में कांस्य पदक जीत कर भी संतुष्ट नहीं हैं मनु भाकर

एजेंसी, नई दिल्ली। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि हांगझोउ में हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर उनकी भावनाएं मिली जुली है और वह इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। भाकर को भारत की ईशा सिंह ने ही पीछे छोड़ दिया था दिया, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इस स्पर्धा में भारत के दो पदक पक्के किए थे। भाकर अभी भी 2026 में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने की तलाश में हैं, जबकि म्यूनिख विश्व कप में सम्राट राणा के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतना उनका अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन ये दोनों स्वर्ण पदक टीम स्पर्धाओं में आए थे। भाकर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''एक और कांस्य पदक। इस पदक को लेकर मेरी मिली-जुली भावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाई, लेकिन साथ ही, मुझे पता है कि मैं इससे भी बेहतर कर सकती थी।''

आईपीएल ने भारत में बदला खेल देखने का नजरिया : नेस वाडिया

एजेंसी, मुंबई। पंजाब किंग्स के सह मालिक नेस वाडिया ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सफलता और इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर कहा कि इस टूर्नामेंट ने भारत में खेलों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल ने न केवल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि खेल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। वाडिया ने यह टिप्पणी आईपीएल की अर्थव्यवस्था पर 'हूलिहान लोकी' की नई रिपोर्ट जारी होने के बाद की। उन्होंने मीडिया राइट्स, टीमों की ग्रोथ और टूर्नामेंट के बढ़ते व्यावसायिक महत्व पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा खेल मंच बन चुका है, जिसने खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और पूरे खेल उद्योग के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।

आईसीसी 2027 वनडे विश्वकप के लिए टीमों का आकार बढ़ाए : मैकडॉनाल्ड

एजेंसी, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2027 वनडे विश्वकप के लिए टीमों का आकार बढ़ाने की मांग की है। इस महीने की शुरुआत में आईसीसी ने नए प्रारूप के साथ टूर्नामेंट का विस्तार करने का फैसला किया था। करीब दो सप्ताह पहले आईसीसी ने घोषणा की थी कि 2027 वनडे विश्व कप 14 टीमों का टूर्नामेंट होगा। इसमें ग्रुप चरण से पहले सुपर सीरीज और सेमीफाइनल से पहले नया सुपर-7 चरण भी होगा। यह 2023 में भारत में खेले गए 10 टीमों वाले वनडे विश्व कप से अलग प्रारूप है। 2023 के विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया ने नौ लीग मैच, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल सहित कुल 11 मैच खेले थे। लेकिन 2027 में चैंपियन बनने वाली टीम को कम से कम 13 मैच खेलने होंगे, जिसमें पांच ग्रुप मैच, छह सुपर-7 मुकाबले, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल शामिल होगा। अगर शुरुआती सुपर सीरीज़ खेलने वाली निचली रैंकिंग की तीन टीमों में से कोई फाइनल तक पहुंचती है, तो चैंपियन टीम को 15 मैच भी खेलने पड़ सकते हैं।

राष्ट्रमंडल खेलः छठे दिन भारत को मिले दो रजत, 12 पदकों के साथ तालिका में नौवें स्थान पर

गुलवीर ने रचा इतिहास, हरजिंद्र ने वेटलिफ्टिंग में दिखाया कमाल

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रमंडल खेल-2026 के छठे दिन भारत ने अपने खाते में दो और रजत पदक जोड़कर कुल पदकों की संख्या 12 पहुंचा दी। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता, जबकि हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा रजत अपने नाम किया।

इन दोनों उपलब्धियों के साथ भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक हो गए हैं। पदक तालिका में भारतीय दल नौवें स्थान पर बना हुआ है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा लगातार कायम है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 35 स्वर्ण, 18 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 80 पदक जीतकर पहला स्थान मजबूत किया है। कनाडा 13 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड 10 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 43 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। मेजबान स्कॉटलैंड 7 स्वर्ण के साथ चौथे, नाइजीरिया पांचवें, मलेशिया छठे, दक्षिण अफ्रीका सातवें और न्यूजीलैंड आठवें स्थान पर हैं। भारत नौवें स्थान पर है, जबकि जमैका शीर्ष-10 में दसवें स्थान पर मौजूद है। भारत को अब आगामी मुकाबलों में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, सहित अन्य स्पर्धाओं से पदकों की उम्मीद रहेगी, जिससे पदक तालिका में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है।

एफआईएच वर्ल्ड कप-2026

भारतीय महिला हॉकी टीम यूरोप रवाना

एजेंसी, बेंगलुरु

भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार सुबह यूरोप के लिए रवाना हुई। एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड 2026 की मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। टीम ने बेंगलुरु से मुंबई की यात्रा की और फिर फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के लिए उड़ान भरी, जहाँ वह इस बड़े इवेंट से पहले अपनी तैयारियों के आखिरी चरण को पूरा करेगी।

फ्रैंकफर्ट में रहने के दौरान, भारतीय टीम 31 जुलाई और 1 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ दो प्रैक्टिस मैच खेलेगी ताकि टीम के तालमेल को बेहतर बनाया जा सके और यूरोपीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला जा सके। ट्रेनिंग कैंप के बाद, टीम 2 अगस्त को एम्स्टर्डम के लिए रवाना होगी ताकि नीदरलैंड में वर्ल्ड कप की अपनी तैयारियों को जारी रख सके। भारत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद पूल डी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगा।

◆ फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के खिलाफ टीम खेलेगी दो प्रैक्टिस मैच

टीम के रवाना होने से पहले, कप्तान सलीमा टेटे ने टीम की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा, 'पूरी टीम आने वाली चुनौती के लिए उत्साहित है। हमारी ट्रेनिंग अच्छी रही है, और अब उस लय को प्रैक्टिस मैचों और फिर वर्ल्ड कप में भी बनाए रखना है। अपने पहले मैच में चीन का सामना करना एक अहम परीक्षा होगी, और हम टूर्नामेंट की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं। एक टीम के तौर पर, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' जर्मनी में महीनों की तैयारी और अहम ट्रेनिंग (जिसमें मेजबान टीम के खिलाफ दो प्रैक्टिस मैच भी शामिल हैं) के साथ, टीम अच्छी शुरुआत करने के लिए उत्सुक है।

नेपाल में डॉक्टरों का हड़ताल अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल के वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में देशभर के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं ठप हैं। चिकित्सकों ने बुधवार को काठमांडू में प्रदर्शन कर कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल की मांग की।

नेपाल चिकित्सक संघ के नेतृत्व में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने माइतीघर मंडला में विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने नारायणी अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद राम के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

चिकित्सकों ने मंगलवार से ही ओपीडी, नियमित जांच और अन्य सेवाएं बंद कर रखी हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नारायणी अस्पताल के डॉक्टरों ने घटना के विरोध में सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया है। नेपाल चिकित्सक संघ का आरोप है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। संघ अध्यक्ष डॉ. बद्री रिजाल ने कहा कि घटना के पांच दिन बाद भी आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि न्याय की मांग करने वाले चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

जापान में भूकंप से अब तब 13 लोगों की मौत

एजेंसी, टोक्यो। जापान के दक्षिण-पश्चिमी क्यूशू द्वीप के कुमामोटो इलाके में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

◆ शॉपिंग सेंटर में हुए धमाके में दो महिलाओं की गई जान

भूकंप के बाद कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और बचाव अभियान जारी है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भूकंप के बाद कुमामोटो के एक शॉपिंग सेंटर में गैस रिसाव के कारण हुए धमाके में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल अवस्था में मिली। यात्सुशिरो शहर में निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज की मिल की चिमनी गिरने से 11 लोग लापता हो गए हैं। प्रशासन ने कुमामोटो और नागासाकी इलाकों में 2.61 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए करीब 3,600 सेल्फ डिफेंस फोर्स कर्मियों को तैनात किया गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने लोगों को आफ्टरशॉक्स की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

पाकिस्तान के बलोचिस्तान में डिप्टी कमिश्नर समेत चार लोगों की हत्या

एजेंसी, इस्लामाबाद

◆ नुश्की में 31 जुलाई तक बढ़ाया कर्फ्यू

पाकिस्तान के अशांत प्रांति बलोचिस्तान में हथियारबंद लोगों ने बरखान के डिप्टी कमिश्नर समेत चार लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में बाकी तीन स्क्वायड दस्ते के सदस्य बताए गए हैं। इस दौरान प्रांतीय सरकार ने नुश्की जिले में लागू कर्फ्यू की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।

द बलोचिस्तान पोस्ट और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हथियारबंद लोगों ने बरखान जिले में घाटा चौक के पास नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान बरखान के डिप्टी कमिश्नर मुरीद बुगती और उनके बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले गए। बलोचिस्तान के गृहमंत्री के प्रवक्ता के मुताबिक, हथियारबंद लोगों ने बाद में डिप्टी कमिश्नर मुरीद बुगती की हत्या कर दी।

तुर्बत के दारमकोल पेडरक इलाके में आज अज्ञात हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों तीन लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की और मरने वालों की पहचान शाह बेग, अमानुल्लाह और अल्ताफ हुसैन के रूप में की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक संघीय सरकार प्रायोजित डेथ स्क्वायड के सदस्य थे। डिप्टी कमिश्नर और इन तीन लोगों की हत्या की अभी तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

इस बीच बलोचिस्तान के गृह विभाग ने खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए नुश्की जिले में 28 जुलाई की रात आठ बजे लगाए कर्फ्यू की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। गृह विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि कर्फ्यू के दौरान बिना इजाजत घर से बाहर निकलने और घूमने-फिरने पर रोक रहेगी। अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि में लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और गैर-जरूरी यात्रा पर पाबंदी रहेगी। सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल, बचाव और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर के पास होगा। अधिसूचना के मुताबिक, 28 जुलाई को नुश्की के वेस्टर्न बाईपास पर फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्ट पर हमले के बाद हालात खराब बने हुए हैं।

भोपाल में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ बसों पर चढ़े

एजेंसी, भोपाल

मूंग खरीदी, ई-टोकन सिस्टम समेत अन्य मांगों को लेकर भोपाल में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को एम्प्री के पास वीर सावरकर सेतु पर पुलिस ने रोक दिया। बसों की चार लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। कुछ किसान पहले बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर नीचे उतार दिया। इसके बाद किसान वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

प्रदर्शन स्थल पर कुछ किसान अर्धनग्न होकर विरोध जता रहे हैं और सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगें पूरी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ किसान रातभर जागने के बाद आराम करते नजर आए। दाल-बाटी बनाकर सड़क पर ही लंच का इंतजाम किया। किसानों के समर्थन में जेन-जेड भी प्रदर्शन में शामिल हैं। किसानों ने सरकार की 'सद्बुद्धि' के लिए हवन भी किया और आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी है। इससे होशंगाबाद रोड और आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नर्मदापुरम रोड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर संवाद के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल मंत्रियों का दल किसानों से बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों के साथ है, लेकिन आम जनता को परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

मणिपुर में यूएनएलएफ (पी) संगठन का उग्रवादी गिरफ्तार

एजेंसी, इंफाल। सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई को चलाए गए उगाही विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ (पी) के एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान संगठन के सार्जेंट मेजर समाद्रम ज गत सिंह उर्फ थम्बालजाओ उर्फ रोमन (49) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से थौबल हाओखा का निवासी है और वर्तमान में काकचिंग जिले के तोकपा चिंग मयाई लैकाई क्षेत्र में रह रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे अरोंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह उगाही गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। मामले में आगे की जांच जारी है।

देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाएगी एनएचएआई, अभियान शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बहाल करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देशभर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य राजमार्गों पर अवैध निर्माण, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और अनधिकृत पहुंच को हटाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एनएचएआई, पीआईयू राजकोट ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 693 किलोमीटर राजमार्ग का सर्वेक्षण कर 1,403 नोटिस जारी किए गए। इनमें अवैध संरचनाएं, अनधिकृत वाणिज्यिक पहुंच और बिना अनुमति बनाए गए मीडियन कट शामिल थे। कार्रवाई के तहत 361 अवैध पहुंच और अतिक्रमण हटाए गए तथा 150 अनधिकृत मीडियन गैप स्थायी रूप से बंद किए गए। यह अभियान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के सहयोग से चलाया गया।

हाल ही में सोमनाथ-द्वारका राजमार्ग पर विशेष अभियान चलाकर बारडिया और 'ऑनेस्ट होटल से हाथी चौक' तक के हिस्से से सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए। मंत्रालय ने कहा कि ये केवल प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के उपाय हैं। अतिक्रमण हटाने से दृश्यता बहाल होती है, यातायात प्रवाह सुधरता है, आपातकालीन सेवाओं को जगह मिलती है और दुर्घटनाओं की आशंका घटती है।